बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 165 ● नई दिल्ली ● सोमवार 30 जून 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन बी-2/370, सुल्तानपुरी दिल्ली-86

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यकर्ताओं व आमजन संग सुना प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम

चंडीगढ़। हरियाणा के युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और पूरी दुनिया में भारत की सफलता की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि 'मन की बात' केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह पूरे देश और जनता का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया के कोने-कोने से प्रेरणादायक बातें साझा करते है, जो सभी को उत्साहित और प्रेरित करती हैं। खेल राज्य मंत्री रविवार को पलवल में पार्टी कार्यकर्ताओं व आमजन के साथ प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम का 123 वां संस्करण को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि वे हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम अवश्य सुनते हैं, जिससे उन्हें प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है।

वृद्ध आश्रम में अमानवीय व्यवहार : ट्रस्ट ने माना- महिला के हाथ बांधना गलती, केयर टेकर को निकाला

नोएडा ।

शहर के सेक्टर 55 स्थित आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम में अव्यवस्था होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस दौरान कल भी पूरे दिन प्रशासन से लेकर वृद्धजनों के बीच गहमा-गहमी बनी रही। वहीं इस मामले को लेकर आश्रम के ट्रस्ट प्रमुखों ने परिवार संग बैठक कर पिछले दो दिनों तक हुई गतिविधि के बारे में बताया और कहा कि जिस केयर टेकर ने महिला के हाथ बांधे वह गलत था, उसे काम से निकाल दिया गया है। शनिवार को दोपहर में आश्रम संचालित करने वाले ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने वृद्धजनों के परिवार संग बैठक की। जहां उन्होंने परिवार को पिछले दो दिनों तक हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि यहां कुल 39 वृद्धों की देखभाल की जाती है। इनको संभालने के लिए कुल 15 केयर टेकर है। उनका कहना है कि वह आश्रम में हर समय मौजूद नहीं रहते हैं। जब उत्तर प्रदेश की महिला आयोग यहां आई थी, तब ट्रस्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद दूसरे दिन वहां से तीन वृद्धजनों को उनके परिवार को बिना सूचना दिए ही सरकारी वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। जबकि उनमें से एक वृद्धजन के परिवार ने ट्रस्ट से पूछा है कि आखिर कोई कैसे उन्हें यहां से बिना जानकारी दिए ले जा सकता है। इसके बाद ट्रस्ट ने दावा किया है कि जिन तीन वृद्धजनों को प्रशासन ले गया था, उनमें से दो को वापस लाया गया, इनमें से एक आश्रम आए गए, वहीं दूसरे वृद्धजन के परिवार उन्हें अपने साथ ले गए। ट्रस्ट की सचिव नीलम मिश्रा ने परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस महिला के हाथ बंधे हुए का वीडियो वायरल हो रहा है, वह महिला दिमागी रूप से अस्वस्थ है। यह बात स्वयं उनके परिवार के लोगों ने लिखकर उन्हें दी थी। हालांकि यह बात तब सामने आई जब यह मामला हाइलाइट हुआ। उन्हें यहां रहते हुए तीन-चार दिन ही हुए थे। उनके व्यवहार से यह सामने आया कि वह दिमागी रूप से अस्वस्थ है। जबकि आश्रम में दिमागी रूप से अस्वस्थ लोगों के रखने की कोई प्रावधान नहीं है। गलती से उन्हें रख लिया गया था, लेकिन इस बीच जब यह सामने आया कि केयर टेकर ने उनके हाथ बांध दिए हैं, तब उस केयर टेकर को काम से निकाल दिया गया।

हर एक-दो हफ्ते में ही बदलते हैं केयर टेकर, कुछ लंबे समय बाद

संवाद सहयोगी ने जब आश्रम में मौजूद केयर टेकर से बातचीत की तो उनमें से एक महिला केयरटेकर ने बताया कि उन्हें आगे यहां आए हुए दो दिन ही हुए हैं। इसी तरह दूसरी महिला केयर टेकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी लगभग चार पांच दिन ही हुए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि जो महिला या पुरुष काम की तलाश में उनके पास आते हैं, उन्हें वह रख लेते हैं।

ट्रस्ट संग बैठक के दौरान परिवारों ने जताया भरोसा

ट्रस्ट के अधिकारियों संग जब वृद्धजनों के परिवारों संग बैठक की तो सभी परिवारों ने ट्रस्ट पर भरोसा जताया। साथ ही कहा कि वह अपने-अपने परिवार के सदस्यों को कहीं दूसरी और शिफ्ट नहीं करना चाहते है। साथ ही करीब ऐसे 21 परिवार शामिल रहे, जिन्होंने अपनी रजामंदी की बात लिखित में पत्र तैयार कर ट्रस्ट को सौंपा है।

वृद्धजनों के परिवार से लेते हैं सिक्योरिटी फीस

ट्रस्ट के सदस्य अमरवीर सिंह ने बताया कि वह वृद्धजनों के परिवार से सिक्योरिटी फीस लेते हैं। ताकि वृद्धजनों की पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखा जाए। आश्रम में बेहतर क्वालिटी का खाना दिया जाता है। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था दुरुस्त रखी जाती है।

जंतर-मंतर पर आप का प्रदर्शन

नई दिल्ली ।

दिल्ली में झुग्गियों के तोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस आयोजन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान केजरीवाल भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, मोदी जी ने लोगों को 'जहां झुग्गी-वहां मकान' की गारंटी दी थी लेकिन उनका मतलब 'जहां झुग्गी-वहां मैदान' था और अब इन्होंने झुग्गियां तोड़कर मैदान बना दिया है। मोदी जी की गारंटी झूठी है। अब आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी मोदी जी की झूठी गारंटियों पर भरोसा नहीं करना है।

रेखा सरकार पर केजरीवाल का हमला

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसी जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी ने अपना आंदोलन शुरू किया था।

जहां झुग्गी, वहां मकान नहीं, जहां झुग्गी, वहां मैदान अरविंद केजरीवाल ने मोदी की गारंटी को कहा फर्जी और झूठी

आज फिर से झुग्गियों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना आंदोलन शुरू किया है। दिल्ली की झुग्गियों में 40 लाख लोग रहते हैं। यदि भाजपा ने दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ना बंद नहीं किया तो रेखा गुप्ता की सरकार पांच साल नहीं चल पाएगी। भाजपा की सरकार ने पांच महीने में दिल्ली की व्यवस्था को बेकार कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि फरवरी में जब आम आदमी पार्टी की सरकार गई थी। उस समय दिल्ली में 24 घंटे बिजली आया करती थी लेकिन अब लंबे-लंबे पावर कट लग रहे हैं। भाजपा मुफ्त बिजली की स्कीम को बंद कर देगी। दिल्ली के निजी स्कूलों ने मनमाना फीस बढ़ाना शुरू कर दिया है जबकि आपकी सरकार में निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा पा रहे थे। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार है। हफ्तों तक पानी नहीं आ रहा। भाजपा सरकार लगातार मोहल्ला क्लिनिको को बंद कर रही है।

भाजपा और कांग्रेस अमीरों की पार्टी : केजरीवाल

केजरीवाल ने आगे कहा कि भाजपा के पांच साल के बाद दिल्ली 50 साल पीछे चली जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा की सरकार एक जैसा ही काम करती है। दोनों दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी काफी झुग्गियों को तोड़ा जाता था। भाजपा और कांग्रेस अमीरों की पार्टी है और वह केवल अमीरों के लिए ही काम करती है। जबकि आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है और अपने 10 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के स्कूल ठीक किए, मोहल्ला क्लीनिक बनाए, बिजली सस्ती की। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, यदि दिल्ली में 40-50 लाख लोगों को भगाने का प्रयास होगा तो हमारे द्वारा आंदोलन की शुरूआत की गई है।

यदि भाजपा की सरकार नहीं मानी तो दिल्ली के 40 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे और जिस दिन 40-50 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर गए, उस दिन रेखा गुप्ता की सरकार तमाम बहुमत के बावजूद गिर जाएगी। उन्होंने आगे कहा, -पिछले 5 महीने से दिल्ली के अंदर बुल्डोजर चल रहे है, गरीबों के सिर से छत छीनी जा रही है, उनके रोजगार छीने जा रहे है। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस चुप क्यों है? राहुल गांधी अब तक इन गरीबों के लिए क्यों नहीं आए? इसका मतलब साफ है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा की मदद की।

जहां झुग्गी वहीं मकान ये हमारी सरकार और पार्टी का संकल्प : कपिल मिश्रा

झुग्गी डेमोलिशन पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी अपनी हार से हताश है वे फिर से वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने 10 साल तक किया। उनको अपनी हार से सबक लेना चाहिए। दिल्ली की जनता एक बदलती हुई दिल्ली के साथ खड़ी है। दिल्ली में कोई झुग्गी ना तोड़ी गई है ना तोड़ी जाएगी। जहां झुग्गी वहीं मकान ये हमारी सरकार और पार्टी का संकल्प है। पक्का मकान झुग्गीवासियों को मिले हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जबतक पक्का मकान उसी जगह पर नहीं मिलता तब तक दिल्ली में किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जा रहा है। केजरीवाल का गैंग बार-बार झूठ बोलता है। उसी झूठ के कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा है।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बरसे बदरा, तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत

नई दिल्ली । दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज फिर बारिश देखने को मिली। इस पहले शनिवार दोपहर को दिल्ली-एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। इससे पारा भी सामान्य से नीचे चला गया। शनिवार को दोपहर तक खिली धूप के कारण लोग गर्मी से परेशान थे। दोपहर बाद काले बादल छा गए, जिसके बाद कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने रविवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया था। साथ ही उम्मीद जताई है कि दो जुलाई तक दिल्ली में बारिश हो सकती है। रविवार सुबह से गुरुग्राम में रुक-रुक कर हो रही बारिश ने उमस से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक और बारिश होने की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर का मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। जिससे वातावरण में ठंडक बनी हुई है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सेक्टर 14, सेक्टर 5, सेक्टर 9, बसई, माता रोड समेत ओल्ड गुरुग्राम जैसे प्रमुख इलाकों में पानी भर गया। जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है और कई वाहन पानी में बंद होते नजर आए।

अमृतसर से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्री ने किया हंगामा, एयर होस्टेस को दिखाई चप्पल

नई दिल्ली । अमृतसर से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान में एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि यात्री शराब के नशे में था। इस दौरान उसने सह-यात्रियों के साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया। चालक दल के सदस्यों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एयर होस्टेस को चप्पल दिखाई। विमान के दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचने के बाद एअर इंडिया के कर्मचारियों ने आरोपी यात्री को सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया। एअर इंडिया के सूत्रों ने बताया कि घटना 28 जून को अमृतसर से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या एआई 454 में हुई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पत्नी-बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था। लैंडिंग के समय उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी और खड़े होकर एक सहयात्री से झगड़ा करने लगा। इस दौरान एक अन्य यात्री ने भी आरोपी की शिकायत की। चालक दल के सदस्यों ने विमान के उतरने के दौरान दूसरे यात्री को बिजनेस क्लास की सीट पर बैठा दिया। बाद में उसकी शिकायत पर पायलट ने एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों को घटना की जानकारी दी और आरोपी को उनके हवाले कर दिया।

देश में 95 करोड़ लोगों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा का लाभ, पीएम मोदी ने 2015 के भी बताए आंकड़े

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश में 95 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रहे है, जबकि साल 2015 में यह आंकड़ा 25 करोड़ ही था। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड को संबोधित किया। इसी में पीएम मोदी ने 95 करोड़ लोगों के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में होने की बात कही।

आईएलओ की रिपोर्ट का दिया हवाला

प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया है कि भारत की 64 प्रतिशत आबादी किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रही है। प्रधानमंत्री ने कहा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत की 64 प्रतिशत से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल रहा है। आज देश के 95 करोड़ लोग किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। साल 2015 तक ये आंकड़ा 25 करोड़ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुनिया में सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा दायरा है।

हर कदम के साथ मजबूत होगा भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय की भी यह अच्छी तस्वीर है। ये सफलता इस विश्वास से आई है कि आने वाला समय और भी अच्छा होगा। भारत हर कदम के साथ मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री ने देश की एक और उपलब्धि की तारीफ की और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के स्वास्थ्य कर्मियों की सफलता है। ट्रेकोमा एक बेहद संक्रमणकारी बीमारी है। प्रधानमंत्री ने कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ आदि तीर्थ यात्राओं को लेकर कहा कि जब कोई तीर्थयात्रा पर निकलता है, तो एक ही भाव सबसे पहले मन में आता है, चलो, बुलावा आया है। यही भाव हमारे धार्मिक यात्राओं की आत्मा है। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम हैं। इनके अलावा, इन यात्राओं का एक और बड़ा पक्ष होता है। ये धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसरों का एक महाअभियान भी होती हैं। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं, उससे ज्यादा लोग तीर्थयात्रियों की सेवा के काम में जुटते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा भी देखी है। ओडिशा हो, गुजरात हो, या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के भाव का प्रतिबिंब है।

इस बार मानसून ने रच दिया नया रिकॉर्ड, दिल्ली सहित पूरे देश में समय से पहले पहुंचा

नई दिल्ली। भारत में इस बार मानसून ने अपने आगमन की टाइमिंग से सबको हैरान कर दिया है। आमतौर पर यह मौसम प्रणाली केरल में 1 जून को दस्तक देती है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेती है। लेकिन इस साल यह सभी अनुमान और आंकड़े पीछे छोड़ता हुआ पहले ही अपने गंतव्य तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल दिल्ली में मानसून ने 30 जून की सामान्य तिथि से एक दिन पहले यानी 29 जून को दस्तक दी। इससे भी बड़ी बात ये रही कि पूरे भारत में मानसून 8 जुलाई की औसत तिथि से नौ दिन पहले यानी 29 जून तक ही फैल चुका था। यह 2020 के बाद पहली बार हुआ है जब मानसून ने इतनी तेजी दिखाई है। पुराने आंकड़ों के अनुसार, 2020 में मानसून ने पूरे देश को 26 जून तक कवर कर लिया था। उस रिकॉर्ड के करीब पहुंचते हुए इस बार भी मानसून ने तेजी दिखाई है। इस बार 2024 में मानसून ने 29 जून तक देशभर को कवर कर लिया, जो काफी असामान्य माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि मानसून इस बार 24 मई को ही केरल पहुंच गया, जो कि 2009 के बाद से सबसे जल्दी दस्तक थी। 2009 में यह 23 मई को केरल पहुंचा था। इसके बाद यह तेजी से देश के अन्य हिस्सों में फैलने लगा। इस साल मानसून को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी मजबूत निम्न दबाव प्रणालियों से गति मिली। इसके चलते यह तेजी से आगे बढ़ा और 29 मई तक मुंबई, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत को कवर कर चुका था। हालांकि शुरुआती रफ्तार के बाद मानसून को एक झटका लगा। 29 मई से 16 जून तक यानी लगभग 18 दिनों तक मानसून की प्रगति में ठहराव आया। यह ठहराव उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने का कारण भी बना । हालांकि मानसून पूरे देश में तेजी से फैला, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसके आगमन में थोड़ी देरी हुई। इसका मुख्य कारण था यहां चल रही एंटी-साइक्लोनिक हवाएं, जिन्होंने मानसून की धाराओं के बहाव को प्रभावित किया।

जंतर मंतर पर आप के विरोध प्रदर्शन पर बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली में नोटंकियां...

नई दिल्ली । दिल्ली में झुग्गियों के तोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी रविवार (29 जून) को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है..क के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए है. आप के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप के प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जब पूछा गया कि रोजगार, नौकरी समेत कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की बीजेपी सरकार का विरोध कर रही है, इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली शहर में नौटंकियां कई जगहों पर चलती रही है, उनको करने दीजिए

कश्मीरी गेट बस अड्डे की पार्किंग पड़ रही महंगी, पंजाब रोडवेज ने बाहर तलाशी जगह

पूर्वी दिल्ली। कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे के अधिक पार्किंग शुल्क से बचने के लिए पंजाब रोडवेज ने सस्ता और अच्छा विकल्प तलाश लिया है। शास्त्री पार्क में नगर निगम की पार्किंग को पंजाब रोडवेज ने अड्डा बनाया है। इसमें मात्र 100 रुपये प्रति बस शुल्क लगता है। इतने खर्चे पर पांच घंटे तक बस खड़ी कर सकते है। पंजाब के विभिन्न शहरों से लंबे सफर के बाद यात्रियों को कश्मीरी गेट बस अड्डे के बाहर उतारने के बाद चालक और परिचालक निगम की पार्किंग का रुख कर लेते है। वहीं पार्किंग में कुछ घंटे सुस्ता कर अपनी थकान उतारते है, फिर यहां से बस अड्डे के अंदर जाकर सवारियां लेकर निकल जाते है। कश्मीरी गेट समेत अन्य अड्डों में बसों की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर पिछले साल दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआइडीसी) ने अड्डे में 25 मिनट बस खड़ी करने के 590 रुपये वसूलने शुरू कर दिए थे। 25 मिनट से ऊपर होते ही 50 रुपये पांच मिनट के हिसाब से अतिरिक्त देने पड़ते हैं। इस हिसाब से एक बार बस अंदर घुसी और चालक-परिचालक दो से तीन घंटे सुस्ताने चले गए तो रोडवेज को 1700 से 2400 रुपये तक का भुगतान बनता था। लंबी दूरी की बसों के चालक-परिचालक के यह मुमकिन नहीं कि वह कश्मीरी गेट बस अड्डे में घुसते ही चंद मिनटों में बस भरकर दोबारा से यात्रा पर निकल पड़े। ऐसे में कश्मीरी गेट बस अड्डे के अंदर बस खड़ी कर उनके लिए सुस्ताना अधिक पार्किंग शुल्क के चलते नुकसानदायक साबित हो रहा था। इस समस्या का हल खोजते हुए पंजाब रोडवेज ने शास्त्री पार्क क्षेत्र में जग प्रवेश अस्पताल के पास डीडीए की जमीन पर निगम की अधिकृत पार्किंग को अपना नया अड्डा बना लिया है। यह पार्किंग बस अड्डे से पांच किलोमीटर दूरी पर है। एक वक्त में पार्किंग में रोडवेज की करीब दस बसें खड़ी रहती है। 24 घंटे में करीब 55 बसें पंजाब से यहां आती है। रोडवेज बस चालकों व परिचालकों के लिए यहां एक टीन शेड में विश्राम स्थल बनाया है। जहां वह नहाने के साथ खाना खाने व आराम करने के साथ फोन चार्ज कर सकते हैं। पार्किंग में मौजूद रोडवेज के बस चालकों ने कहा कि हर एक विभाग चाहता है उसे ज्यादा राजस्व हो। लेकिन बस अड्डे में शुल्क बढ़ने से रोडवेज को घाटा हो रहा था। अधिक शुल्क से बचने के लिए गर्मी में सड़कों पर बसें लेकर खड़े रहते थे। यातायात पुलिस चालान कर देती थी और जाम लगने से अन्य वाहन चालक लड़ते थे। कश्मीरी गेट बस अड्डे में पंजाब रोडवेज के इंचार्ज अमरजीत सिंह ने बताया कि अब बस अड्डे पर 25 मिनट के 590 रुपये का भुगतान ही करना पड़ता है। उसके ऊपर लगने वाले 1200 से 1800 रुपये प्रति बस बच रहे हैं।

मिनटों में चोरी करते थे लग्जरी कारें, पुलिस ने 3 शातिर चोरों को दबोचा

बाहरी दिल्ली।

रोहिणी एएटीएस टीम ने लग्जरी कारें चुराने वाले तीन शातिर चोरों को पकड़ा है। वे जीपीएस ब्लॉक करने के लिए जैमर का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने क्रेटा सियाज थार और किआ सेल्टोस समेत कई गाड़ियां बरामद की है।

लग्जरी कारों की चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को रोहिणी जिला एएटीएस की टीम ने पकड़ा है। कार में लगे जीपीएस को ब्लाक करने के लिए आरोपित सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करते थे। इनके पास से आरोपित से तीन क्रेटा, एक सियाज, एक थार, एक किआ सेल्टोस, अपराध में इस्तेमाल एक आई-10 कार समेत सात खाली आटोमैटिक कार की चाबियां, जीपीएस ब्लाक करने के लिए सिग्नल जैमर, चार ड्राइवर साइड विंडो मिरर समेत अन्य सामान हुए बरामद किए गए हैं। रोहिणी जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप गुप्ता ने बताया कि रोहिणी जिले में एक लग्जरी कार चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। रोहिणी जिला एएटीएस को एक गिरोह के तीन सदस्यों की आवाजाही के बारे में सूचना मिली। जो विजय विहार में आने वाले थे। टीम ने विजय विहार में जाल बिछाकर तीन वाहन चोर को पकड़ लिया। आरोपितों की पहचान सुनील उर्फ राम, वीरेंद्र और गणेश सिंह बिष्ट उर्फ वीर के रूप में हुई। इनके कब्जे से हुंडई क्रेटा कार थाना प्रशांत विहार क्षेत्र से चोरी की हुई मिली। तलाशी के दौरान आरोपित की कार से सिग्नल जैमर, चार ड्राइवर साइड विंडो मिरर और 07 खाली चाबियां भी बरामद हुई। लगातार पूछताछ करने पर आरोपितों ने खुलासा किया कि वे लग्जरी कारों को चुराते थे। उनकी निशानदेही पर दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से चुराई गई पांच और चोरी की लग्जरी कारें भी बरामद की गईं। सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। सभी आरोपित अपने साथियों के साथ चोरी की गई कार में कार चोरी करने आते थे। वे कार खोलने के लिए पिछली खिड़की के पीछे का शीशा तोड़ते थे और उसके बाद अपने पास मौजूद औजार और खाली आटोमैटिक कार की चाबियों की मदद से वे टारगेट कार के लिए नई चाबी तैयार करते थे। चोरी में जीपीएस को ब्लाक करने के लिए सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करते थे। उन्हें चाबी तैयार करने के लिए एक कोड की भी जरूरत होती थी, जिसे वे अपने किसी साथी से लेते थे। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

शराब के नशे में नकली पुलिस बनकर सिक्योरिटी गार्ड की लूटी बाइक, पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा

नई दिल्ली। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट थाना इलाके में 26 जून की शाम एक सिक्योरिटी गार्ड से बाइक लूट के मामले को पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर सुलझा लिया है. इस मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल रहे तीनों आरोपियों को दबोच लिया है जिनकी पहचान गर्वित शर्मा उर्फ सनी (25), प्रशांत कुमार (22) और अनीकेत (23) के रूप में हुई है. ये दिल्ली के पालम, दशरथपुरी और किशनगढ़ इलाके के रहने वाले है. ये सभी काफी पढ़े-लिखे है और इन्होंने क्रमशः बीसीए, बीटेक और एमबीए की पढ़ाई की है. इनके कब्जे से पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक जबकि इनकी निशानदेही पर लूटी गयी स्प्लेंडर बाइक भी बरामद कर ली है. डीसीपी उषा रंगनानी के मुताबिक, तीनों आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड अमरपाल सिंह की बाइक लूट ली थी. घटना 26 जून की शाम तकरीबन साढ़े 7 बजे के आसपास की है जब पीड़ित अमरपाल सिंह, ऐरोसिटी स्थित वर्ल्डमार्क II में ड्यूटी पर जा रहे थे. रास्ते में महिपालपुर अंडरपास के पास एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उन्हें रोका, खुद को पुलिसकर्मी बताया और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया. जब पीड़ित ने पहचान पत्र दिखाने को कहा तो वे पीड़ित से झगड़ने लगे. उन्हें थप्पड़ मारा और उनकी स्प्लेंडर बाइक को लूटकर वे वहां से फरार हो गए.

पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. डीसीपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन टीमें बनाईं. जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सुमित के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सतीश और इंस्पेक्टर अवधेश को सौंपी गई. टीमों ने पालम, एयरपोर्ट और वसंत कुंज की संभावित रूटों की जांच की. जांच में बाइक शकरपुर के रहने वाले सिद्धार्थ के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई. पूछताछ में सिद्धार्थ ने बताया कि यह बाइक उसने एक साल पहले अपने परिचित गर्वित शर्मा को दी थी. पीड़ित ने भी वारदात में सिद्धार्थ की संलिप्तता से इनकार किया.

जिसके बाद पुलिस ने गर्वित शर्मा की तलाश शुरू की. उसकी लोकेशन की निगरानी करते हुए पुलिस ने आखिरकार उसे पालम इलाके से धर दबोचा. पूछताछ में गर्वित ने न केवल अपराध स्वीकारा, बल्कि अपने साथियों प्रशांत और अनीकेत के नाम भी उजागर कर दिए. आरोपी गर्वित ने बताया कि वह अपने दोस्त प्रशांत के साथ अनीकेत से मिलने किशनगढ़ गया था. जहां तीनों ने शराब पी और नशे में मोटरसाइकिल लूटने का प्लान बनाया.

योजना के अनुसार, वे ऐरोसिटी पहुंचे और अमरपाल को निशाना बनाया. लूट के बाद प्रशांत लूटी गई स्प्लेंडर बाइक लेकर भागा जबकि वह और अनीकेत अपनी बाइक पर मौके से फरार हो गए. बाद में डर के मारे उन्होंने लूटी गई बाइक को जनक सिनेमा के पास छोड़ दिया. गर्वित की निशानदेही पर पुलिस ने अनीकेत को किशनगढ़ से और प्रशांत को दशरथपुरी से दबोच लिया. दोनों ने पूछताछ में अपराध कबूल लिया. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूटी गई बाइक समेत वारदात में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर जब्त कर लिया. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता

भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना है कि ''हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय,विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।'' इसमें तीन शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता इमरजेंसी काल के दौरान 1976 में जोड़े गये। यह कार्य तत्कालीन संसद द्वारा 42वां संशोधन करके किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह (महासचिव) श्री दत्तात्रेय होसबोले ने इनमें से दो शब्दों समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता को हटाये जाने की वकालत की है और कहा है कि 26 नवम्बर, 1949 को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिये गये संविधान में ये शब्द नहीं थे। श्री होसबोले ने अखंडता शब्द पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है। उनके इस बयान पर देश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है जो किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के लोकसभा में विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी ने इसे लेकर आरोप मढ़ दिया है कि भाजपा व संघ के लोग संविधान नहीं चाहते बल्कि वे हिन्दू मनुस्मृति चाहते हैं। संघ का विश्वास निश्चित रूप से हिन्दुत्व में है मगर उसकी राष्ट्रभक्ति पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। अतः श्री राहुल गांधी को भी संघ पर आरोप लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। हमें यह घटना भी याद करनी चाहिए जब 2002 के आसपास केन्द्र की भाजपा नीत वाजपेयी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री स्व. प्रमोद महाजन ने लोकसभा में सदन के सदस्यों के बीच संविधान की हस्तलिखित कापियां बांटी थीं। इसे तब श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने सुन्दर लेख में लिखा था और उस पर भगवान राम के लंका विजय से लौटते हुए चित्रों के साथ अन्य महापुरुषों के चित्र भी थे जिन्हें संविधान की हस्तलिखित कापी को सुन्दर बनाने हेतु नन्द लाल बोस जैसे प्रतिष्ठित चित्रकार ने बनाया था। इसी हस्तलिखित कापी पर उस समय के महान राजनीतिज्ञों के हस्ताक्षर थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। श्री महाजन ने तब संसद में तर्क रखा था कि संविधान की यह प्रति बताती है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द की कोई जरूरत नहीं है और जहां तक भारत के समाजवादी देश होने का सम्बन्ध है तो 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण की नीति चल रही है वह बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है अतः इस शब्द की भी कोई जरूरत नहीं है।

देखा जाये तो भारत के समाजवादी नीतियों पर चलने का तब कोई तर्क नहीं था क्योंकि वाजपेयी सरकार घाटे में चलने वाली सरकारी कम्पनियों को पूंजीपतियों को बेच रही थी। इस प्रकार भारत का आर्थिक दर्शन पूंजीवाद से जुड़ गया था परन्तु तत्कालीन विपक्ष ने उसे संसद में बुरी तरह आड़े हाथों लिया था और कहा था कि संविधान की मूल प्रति में तो अकबर व टीपू सुल्तान के भी चित्र हैं और पूरा भारतीय संविधान समाजवाद का ऐसा खुला प्रपत्र है जिसमें समाजवादी नीतियों की वकालत की गई है और प्रत्येक नागरिक को बराबर का दर्जा दिया गया है और आर्थिक समानता लाने की बात कही गई है। इसलिए समाजवादी शब्द का प्रस्तावना में जोड़े जाने का उद्देश्य पूरी तरह तर्कसंगत व समयोचित है। मगर तब यह बात आगे नहीं खिंची और बहस के दावों व प्रति-दावों में ही सिमट कर रह गई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी इन दोनों शब्दों को जोड़े जाने के पक्ष में निर्णय दे चुका है। इसके साथ यह भी सत्य है कि 42वें संशोधन की विभिन्न उपधाराओं में इमरजेंसी काल के दौरान ही नागरिकों के कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। इससे पहले केवल नागरिकों के अधिकारों की बात ही संविधान में थी। नागरिकों के मूल अधिकारों की बात संविधान की प्रस्तावना भी करती है। वस्तुतः प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है जिसमें लक्ष्यों को अभिव्यक्त किया गया है। मगर श्री होसबोले के कथन के पीछे भारत की जमीनी सच्चाई है। भारत की हिन्दू संस्कृति स्वयं में ही धर्म या पंथ निरपेक्ष है। हिन्दुओं में सैकड़ों तरीकों की उपासना पद्धतियां हैं। कोई साकार ब्रह्म का उपासक है तो कोई निराकार ब्रह्म का। कोई ईश्वर को सगुण मानता है तो कोई निर्गुण। हजारों की तादाद में देवी-देवता हैं और कुल देवता हैं। अतः हिन्दू होना ही स्वयं में धर्मनिरपेक्षता की गारंटी होती है। अब सवाल यह है कि हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू राज में क्या अन्तर है? हिन्दू राष्ट्र इसकी संस्कृति का वाहक है जबकि हिन्दू राज प्रशासनिक प्रणाली को संकीर्णता में बांध देता है। इस भेद को समझने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान एक समान अवसर प्रदान करने की वकालत करता है और यह भी उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए।

अतः यह समाजवादी धारा का पोषक है इसलिए प्रस्तावना में समाजवादी शब्द रहना किस लिए जरूरी हो सकता है?आखिरकार हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच-समझ कर ही समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्दों को नहीं रखा होगा। जहां तक राष्ट्रीय अखंडता का सवाल है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य निर्दिष्ट किये जाने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। संविधान हर नागरिक के साथ न्याय करने की भी गारंटी देता है। समाजवादी व्यवस्था में इसी की गारंटी तो दी जाती है जो कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों में है। संविधान में इन दो शब्दों का महत्व आनुषंगिक ज्यादा है। क्योंकि आज भी मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को दो वक्त का मुफ्त भोजन सुलभ करा रही है। यह सस्ता बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के बीच से ही निकला है।

सरकार जी का 35 मिनट का फोन कॉल

हाल में ही खबर थी कि हमारे सरकार जी ने अमरीका के सरकार जी से पैंतीस मिनट टैलीफोन पर बातचीत की। यह टैलीफोन पर बात करने का इतिहास बहुत ही पुराना है। पुराने जमाने में रंगून से फोन आता था। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टैलीफून। तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। उसके बाद की फिल्मों में भी हीरो हीरोइन फोन पर गाने गाते रहे हैं। जैसे सुजाता में हीरो हीरोइन को फोन पर सुनाता है, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दीये। ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। बाकी के कुछ टेलीफोनिक गीत गुणी पाठक खुद ढूंढ सकते हैं। इससे पहले भी सरकार जी की ट्रंप जी से फोन पर बात हुई थी। तब हुआ यह था कि हमारे सरकार जी कनाडा गए थे। जी सेवन की कार्यवाही देखने। वहाँ पर सरकार जी को दर्शक की तरह से बुलाया गया था। ऐन टाइम पर सरकार जी को कनाडा के सरकार जी ने बुलवा लिया। और सरकार जी वहाँ इतने उतावले मार कर बैठे कि बाकी सभी मुस्करा कर रह गए। अमरीका के सरकार जी भी वहाँ पर थे। पर जब अमरीका के सरकार जी, मतलब ट्रंप जी को पता चला कि हमारे सरकार जी भी वहाँ पधारने वाले हैं, तो वे हमारे सरकार जी के वहाँ पहुंचने से पहली रात को ही खिसक लिए। मतलब अमरीका वापस लौट गए। जरूरी काम था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को दावत देनी थी। सच में, दोस्ती हो तो ऐसी हो। भले ही एक दूसरे से कभी कहा जाओ पर फोन पर बात तो करते रहो। तो ट्रंप जी ने सरकार जी को फोन लगा दिया। ट्रंप जी ने हमारे सरकार जी से कहा कि जब यहाँ तक आए हो, तो हमारे यहाँ भी आ जाओ। हम तो पड़ोस में ही हैं। कुछ गप शप कर, लंच-डिनर करके जाना। हमारे सरकार जी को दो ही चीजों का तो शौक है। एक पहनने का और दूसरा खाने का। और हाँ, बातें बनाने का भी शौक है। ये बात तो उनके भक्त लोग भी मानते हैं। एक आदमी जिस पर पूरे देश का भार हो, एक छुट्टी तक नसीब न हो, इतने शौक तो पाल ही सकता है। और खाने का तो इतना शौक है कि पड़ोसी के यहाँ बिन बुलाये बिरयानी खाने चले गए। पर सरकार जी ने इस बार कंट्रोल किया। दोस्त के बुलाने पर भी दावत का मोह त्याग दिया। जब आदमी इतना त्याग करे तो उसका गुणगान तो बनता ही है। तो सरकार जी ने अपने द्वारा ट्रंप के निमंत्रण को ठुकराने का गुणगान देश की जनता के सामने किया भी। उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रंप भईया को समझाया कि तुम्हारा खाना और गप शप तो बाद में दूसरी बार भी होती रहेगी। अभी तो महाप्रभु की धरती पर जाना जरूरी है। पर इस बार सरकार जी ने स्वयं फोन किया। इस बार फोन करने की बारी सरकार जी की ही थी। असली वाली दोस्ती ऐसी ही होती है। एक बार फोन मैं करूँ तो एक बार तुम। तो सरकार जी ने ट्रंप जी को फोन किया। सरकार जी ने स्वयं बताया कि पैंतीस मिनट बात हुई। वैसे सरकार जी की उस बातचीत को हम सतरह मिनट की भी मान सकते हैं।

सम्पादकीय...

होसबोले साहब की संविधान की कटाई-छंटाई की डिमांड

ये लो कर लो बात। आरएसएस के नंबर टू, होसबोले साहब ने जरा सी संविधान की कटाई-छंटाई की डिमांड क्या कर दी और खेती-किसानी को छोड़कर बाकी सब का पूरा ध्यान रखने वाले कृषि मंत्री, शिवराज बाबू ने जरा सा मुंह खोलकर बागवानी डिपार्टमेंट वाली उनकी डिमांड का समर्थन क्या कर दिया, विरोधियों ने मार तमाम हल्ला मचा दिया। ये तो संविधान को बदलना चाहते हैं। ये तो संविधान के विरोधी हैं। ये अंबेडकर का संविधान बदल देंगे; और भी न जाने क्या-क्या? लेकिन, यह झूठ है। सफेद झूठ। इन विरोधियों ने ऐसा ही प्रचार चुनाव के टैम पर भी किया था। तब भी इन्होंने संविधान बदले जाने का ऐसा ही डर फैलाया था। तब पब्लिक इनके झांसे में आ भी गयी। कहां मोदी जी चार सौ पार जा रहे थे और कहां ढाई सौ से नीचे ही अटक गए। वह तो भला हो नीतीश, चंद्रबाबू और चिराग बाबू का कि किसी तरह सरकार बनाने का जुगाड़ हो गया। वर्ना संविधान का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व वर्तमान से भूतपूर्व हो जाता। शुक्र है कम से कम फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है। देश की सरकार वाला चुनाव जो करीब नहीं है। सच्ची बात यह है कि नीतीश, चंद्रबाबू, चिराग की तिकड़ी सलामत रहे, पब्लिक बहुत नाराज भी हो जाए, तब भी मोदी जी का कुछ उखाड़ नहीं सकती है। जब चार सौ पार का ढाई सौ करके भी पब्लिक कुछ नहीं उखाड़ पायी, तो बिना चुनाव के पब्लिक क्या ही कर सकती है? उल्टे चुनाव आयोग मुस्तैद रहे, राज्यों के चुनावों की ट्राफी जीत-जीत कर मोदी जी, पब्लिक को ही शर्मिंदा करते रहेंगे कि इससे अच्छा तो अगलों को चार सौ पार ही करा देती। कम से कम हर रोज यह तो नहीं सुनना पड़ता कि पब्लिक अब, तब की गलती सुधार रही है! फिर जैसा हमने शुरू में ही कहा, होसबोले साहब ने संविधान में जरा सी काट-छांट की डिमांड की है। काट-छांट की डिमांड को संविधान बदलने की डिमांड से कन्फ्यूज क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि चुनाव के टैम पर मोदी जी की पार्टी के चार सौ से ऊपर उम्मीदवारों में से चार यानी सिर्फ एक फीसद ने इसका एलान किया था कि चार सौ पार जाएंगे, संविधान बदलवाएंगे; संविधान में जरा से फेरबदल की उनकी डिमांड को, संविधान बदलने की कोशिश मान लिया जाएगा? या सिर्फ इसलिए कि जब पचहत्तर साल पहले संविधान बना था, तब होसबोले साहब के संगठन ने और शिवराज सिंह के मातृ संगठन ने, उसे भारतीय संविधान मानने से ही इंकार कर दिया था; तो क्या उस भारत के उस अभारतीय संविधान में हर काट-छांट को, आज उसका तख्ता पलटने की ही कोशिश मान लिया जाएगा? यह तो न्याय नहीं है। आखिर, काट-छांट, काट-छांट है और बदलना या पलटना, कुछ और ही होता है। अगर संविधान बदलने की ही डिमांड करनी होती तो होसबोले साहब को कौन रोक रहा था? आखिर, उनके पुरखों ने पूरा संविधान बदलने की डिमांड की ही थी और छाती ठोक कर की थी। आंबेडकर के संविधान के खिलाफ जूलूस निकाले थे। आंबेडकर को गालियां दी थीं। नेहरू के संग उनके पुतले जलाए थे। और इतना ही नहीं, मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाए जाने की डिमांड भी रखी थी। जो डिमांड पचहत्तर साल पहले कर सकते थे, आज करने से उन्हें कौन रोकने वाला था? उल्टे अब तो उनका राज भी है। उनकी अपनी पार्टी, एक अंक की संख्या वाली पार्टी से बढ़कर, अब ढाई सौ सीटों तक तो अकेले ही पहुंच चुकी है। फिर थोड़ा-बहुत किंतु-परंतु कर के तिकड़ी भी घुमा-फिराकर संविधान बदलने के लिए भी राजी तो हो ही जानी थी। तब भी, होसबोले साहब ने संविधान में सिर्फ काट-छांट की डिमांड की है। यह संविधान पलटने की नहीं, उसके सुंदरीकरण की डिमांड है। जैसे इमर्जेंसी में संजय गांधी का बुलडोजर, दिल्ली का सुंदरीकरण कर रहा था, वैसे ही संविधान का सुंदरीकरण करने की डिमांड की जा रही है और वह भी बिना बुलडोजर के; सिर्फ पौधों को छांटने वाली बड़ी कैंची के प्रयोग के जरिए। संविधान से सचमुच प्यार करने वालों को तो होसबोले साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बुलडोजर चलाने का मौका था, फिर भी सिर्फ झाड़ की छंटाई वाली कैंची चलाने की डिमांड की है। क्या सचमुच भारतीय संविधान एक बेतरतीब झाड़ ही नहीं हो रहा है? क्या उसके नीचे सेकुलरिज्म से लेकर सोशलिज्म तक की जंगली झाड़ियां नहीं उग आयी हैं? भारत जैसे देश में इन विजातीय चीजों का क्या काम? सेकुलरिज्म का क्या काम? सोशलिज्म का क्या काम? इंसान को इंसान मानने वाले, हर इंसान को बराबर मानने वाले, इंसान को सबसे ऊपर मानने वाले, इन परदेसी दर्शनों का क्या काम? इंसान की बराबरी का क्या काम? जब हमारे पास मनुस्मृति है, जो हमें उसके सिवा किसी न्याय, स्वतंत्रता, समता से क्या काम? और बंधुता? वह किस चिड़िया का नाम है? ज्यादा न सही, संविधान की उद्देशिका में कम से कम सेकुलरिज्म की जगह हिंदू सर्वोच्चता और समता तथा बंधुत्व की जगह, वर्णव्यवस्था को तो रखा ही जा सकता है। कब तक हम धर्मनिरपेक्षता, समता, बंधुता जैसे विदेशी विचारों को ढोते रहेंगे और स्वतंत्रता-संप्रभुता को भी? विदेशी गुलामी की इन निशानियों को कब मिटाया जाएगा।

भगवान भरोसे चल रहे हैं भारतीय एयरपोर्ट?

त्रिदीब रमण

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की त्रासदी के जख्म भले ही अभी-अभी उभरे ताजा हों, पर लगता है इसके बावजूद भी विमानन मंत्रालय अपने पुराने ढर्रे पर ही चलने को मजबूर है। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि आज की तारीख में भी कम से कम डेढ़ दर्जन भारतीय एयरपोर्ट को 'रेग्यूलर एयरपोर्ट डायरेक्टर' की कमी खल रही है। उनकी जगह 'टेम्पररी एयरपोर्ट डायरेक्टर' से ही काम चलाया जा रहा है। कई एयरपोर्ट पर तो सेफ्टी व सिक्योरिटी के दायित्व सम्भालने वाले अफसरों की कई पोस्ट खाली पड़ी हैं। सनद रहे कि एयरपोर्ट डायरेक्टर का किसी भी एयरपोर्ट के सुचारू व सुरक्षित परिचालन में सबसे अहम रोल होता है, अगर रेग्यूलर एयरपोर्ट डायरेक्टर की गैर मौजूदगी की बात हो तो आप मिसाल के तौर पर नार्थ में प्रयागराज, गोरखपुर, मैसूर से रायपुर का नाम ले सकते हैं, साउथ में तिरुपति, तूतीकोरिन व राजा मुंद्री एयरपोर्ट, नार्थ-ईस्ट में डिब्रूगढ़, सिल्चर, जोरहाट, पश्चिम में गोवा और राजकोट एयरपोर्ट का नाम ले सकते हैं जहां रेग्यूलर एयरपोर्ट डायरेक्टर नहीं हैं। आने वाले दिनों में कोलकाता, इंदौर, जम्मू, पुणे, देहरादून के भी रेग्यूलर एयरपोर्ट डायरेक्टर रिटायर होने वाले हैं या उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। सूत्रों की मानें तो उनकी जगह लेने के लिए डायरेक्टर की सलेक्शन प्रक्रिया भी कई महीनों से लंबित पड़ी हुई है। ज्यादातर जगहों पर जहां से एयरपोर्ट डायरेक्टर की विदाई होती है वहां यह जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर वहां के वरिष्ठतम अधिकारी के सुपुर्द कर दी जाती है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह कि वेस्टर्न रीजन के पास कोई रीजनल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही नहीं है। इसी तरह मेंटेनेंस और ऑपरेशंस में भी कई पोस्ट वर्षों से खाली पड़ी हुई हैं। यहां तक कि रेग्यूलर सेफ्टी ऑफिसर की भी भरपाई अन्य विभागों से लोगों को लाकर की जा रही है, जबकि विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि 'सेफ्टी ऑफिसर की एक खास तरह की ट्रेनिंग होती है, उन्हें ऐसी किसी ट्रेनिंग के बाद ही कोई महती जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।' डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय जो कि एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। उसने अपनी ताजा जांच में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा की बड़ी खामियों को उजागर किया है। अहमदाबाद हादसे के तुरंत बाद से ही डीजीसीए एक के बाद एक कई छोटे-बड़े एयरपोर्ट की जांच में जुटा है, जहां उसे तमाम स्तरों पर खामियां मिल रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि विमानन कंपनियां और हवाई अड्डों पर ऑपरेटर के तौर पर सेवाएं देने वाली कंपनियां नियमों की भारी अनदेखी कर रही हैं, जो आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसके अलावा बीसीएएस यानी 'ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी' जिसका काम एयरपोर्ट का ऑडिट करना भी है, डीजीसीए के साथ-साथ यहां भी मैनपॉवर की भारी कमी देखी जा सकती है। सो, ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी ही है कि क्या भगवान भरोसे चल रहे हैं भारतीय एयरपोर्ट? रनवे पर रबर डिपॉजिट भी बन सकता है दुर्घटना का कारण- बारिश के मौसम में रनवे मैंटेनेंस का काम और भी जरूरी व चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि रनवे पर बारिश का पानी ठहरने की वजह से फिसलन हो सकती है ऐसे में लैंडिंग या टेकऑफ कर रहे विमानों के पायलट को भी खास सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे मौसम में रनवे मैंटेनेंस का काम सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। आमतौर पर जब विमानों की लैंडिंग होती है तो रनवे पर टायरों के रबर डिपोजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिसका असर रनवे की 'फ्रिक्शन वैल्यू' पर पड़ता है या आसान शब्दों में कहा जाए तो लगातार रबर डिपॉजिट की वजह से रनवे की चिकनाहट बढ़ जाती है और इससे 'लैंडिंग' या 'टेकऑफ' के दौरान विमान के रनवे पर फिसलने का खतरा बना रहता है। आमतौर पर रनवे की फ्रिक्शन वैल्यू को नियमित तौर पर मापा जाता है, इसका 'विजुअल ऑब्जरवेशन' भी होता है, इसके अलावा भी अगर इस पर कहीं दरार वगैरह दिखती है तो उसकी फौरी मरम्मत भी की जाती है। बाकी रनवे से रबर डिपॉजिट को मैनुअली या फिर एक खास मशीन द्वारा साफ किया जाता है चूंकि इस मशीन की लागत बहुत ज्यादा है सो, हर एयरपोर्ट पर उसे रखना संभव नहीं हो पाता। सो, इस मशीन को अलग-अलग जोन में रखा जाता है और खास एयरपोर्ट के डिमांड के हिसाब से उसे वहां भेजा जाता है। कई बार मशीन के वहां पहुंचने में देर हो जाती है तो निर्दिष्ट एयरपोर्ट मैनुअली ही रबर डिपॉजिट हटाने का प्रयास करते हैं। अगर 'टच डाउन जोन' (जहां विमान का पहिया रनवे को टच करता है) का फ्रिक्शन वैल्यू तयशुदा सीमा के अंदर हो तो यह वहां विमान उतारने के लिए उपयुक्त है। जिस टच डाउन जोन का फ्रिक्शन वैल्यू तयशुदा सीमा का उल्लंघन कर रहा होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को उसे नोटिफाई करना पड़ता है। फिर 'नोटम' होकर यह सूचना विमान के पायलट तक पहुंच जाती है, पायलट ऐसे नोटिफाइड एरिया को अपना टच डाउन जोन नहीं बनाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। दिल्ली में विकास और आईएएस अफसर – दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई में भाजपा सरकार सभी विभागों को मजबूती से चलाने और दिल्ली में शानदार काम करने के लिए देशभर के कोने-कोने से टॉप क्लास आईएएस अफसरों को चार्ज दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता की अगुवाई में काम करने वाले ज्यादातर मंत्रियों का प्रशासनिक अनुभव शून्य है। चार आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनकी भूमिका सबसे अहम है। ये सभी पॉलिसी बनाने से लेकर इसे लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसे सीएम के प्रिंसिपल सैक्रेटरी ए. अन्बारसु 96 बैच के आईएएस अफसर हैं जो पुडुचेरी से यहां लाए गए हैं। ठीक वैसे ही दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ 2006 बैच के यूपी कैडर के आईएएस कौशल राज शर्मा को बनाया गया है। इसी कड़ी में अन्य अफसर भी मोर्चों पर डटे हुए हैं। सो उन्हें सही कामकाज के लिए ये अफसर अलग-अलग विभागों में मोर्चा संभाले हुए हैं। पीडब्ल्यूडी हो या दिल्ली जल बोर्ड ये सभी अफसर फ्री हैंड लेकर काम कर रहे हैं और सबको पता है कि उन्हें ऊपर से ?मिले आदेशों का पालन करना है। अब सभी विभागों में कामकाज तेजी से हो रहे हैं, यानि दिल्ली तेजी से विकास की सही राह पर है। बिहार में कांग्रेस राम भरोसे- बिहार कांग्रेस के नए-नवेले अध्यक्ष राजेश राम अपने करीबियों के समक्ष कई-कई दफे इस बात का दावा कर चुके हैं कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अपने 85 फीसदी टिकट एससी, एसटी, पिछड़े-अति पिछड़े व मुसलमानों को देगी, यानी कि सवर्ण जातियों को कांग्रेस के कोटे से सिर्फ 15 फीसदी टिकट ही दिया जाएगा। समझा जाता है कि आरजेडी व वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में इस बार कांग्रेस के पास 40 सीटें आ सकती हैं, इसका 15 फीसदी यानी राम साहब की मानें तो अगड़ी जातियों के लिए सिर्फ 6 सीटों की ही गुंजाइश है। कांग्रेस के पास अभी 5 निर्वाचित फॉरवर्ड विधायक हैं, इन सबको फिर से टिकट देना संभवतः हाईकमान की मजबूरी हो सकती है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व अगड़ी भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले अखिलेश सिंह अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, इसकी अनदेखी शायद कांग्रेस शीर्ष के लिए संभव नहीं होगा। चर्चित पत्रकार रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पांडेय ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात लालू यादव से करवाई थी, ब्रजेश भी कांग्रेस टिकट के एक प्रबल दावेदार हैं। कहते हैं राजेश राम की ताजा मंशाओं को भांपते अगड़ी जातियों का अभी से कांग्रेस से मोह भंग होना शुरू हो गया है। कांग्रेस के कई फॉरवर्ड नेताओं ने तो सदाकत आश्रम का रुख करना ही छोड़ दिया है, वहीं राजद का कांग्रेस पर दबाव है कि वह ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न दे। राजेश राम जो औरंगाबाद की कुटुम्बा रिजर्व सीट से मौजूदा विधायक हैं, वे इस बार यहां से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उन्होंने पार्टी शीर्ष को अभी से ताकीद कर दिया है कि चूंकि उन्हें घूम-घूम कर पूरे बिहार में कांग्रेस के पक्ष में अलख जगाना है तो वे एक सीट से बंध कर नहीं रहना चाहते। लुधियाना उप चुनाव के हालिया नतीजों ने भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को फिर से करीब आने का मौका दिया है। हालांकि अकाली दल काफी पहले से भाजपा के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने में जुटा था। इसके बाद सुखबीर सिंह बादल ने अपने 'मैन फ्राईडे' कहे जाने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा के मार्फत फिर से भाजपा से पींगें बढ़ानी शुरू कर दी। सिरसा फिलवक्त दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और 2021 में ये व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए शिरोमणि अकाली दल छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में जिस तरह से छोटी-छोटी हार्डलाइनर पार्टियों का अभ्युदय हुआ है, इन पार्टियों ने अकाली दल की सियासी जमीन को और बंजर बनाने का काम किया है। सो, ऐसे में अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के लिए भाजपा एक बड़ी तारणहार साबित हो सकती है। हालिया लुधियाना उप चुनाव में जहां आप के संजीव अरोड़ा 35179 वोट पाकर विजयी रहे, भाजपा यहां 20323 वोट पाने में कामयाब रही, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 8203 वोट मिल गए तो कांग्रेस को 24542 मतों से ही संतोष करना पड़ा। अब अकाली दल-भाजपा को मिला दें तो दोनों के संयुक्त वोट 28526 हो जाते हैं यानी राज्य की दूसरी सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर यह गठबंधन उभर सकता है, भाजपा यह जानती है, सुखबीर के लिए भाजपा को यह बताते रहना उनकी सियासी मजबूरी है। और अंत में – जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भाजपा के करीबी रिश्ते रहे हैं। सो, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों के जिन प्रतिनिधिमंडलों को अलग-अलग देशों में भेजा गया था उसमें से एक अहम दल की रहनुमाई इनको सौंपी गई थी। अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार के न्याय मंत्रालय ने आनन-फानन में संजय झा की दोनों वकील बेटियों यानी अद्या झा व सत्या झा को केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैनल 'ए' पैनल में शामिल कर लिया है। सनद रहे कि संजय झा की दोनों बेटियां दो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से एलएलएम की डिग्री लेकर भारत आई हैं।

जारी है आपातकाल की शव परीक्षा

अनिल जैन

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ दिनों पहले यूरोप के देशों पर तंज करते हुए कहा था कि जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो साझेदार ढूंढते हैं, उपदेश देने वाले नहीं। अब उन्होंने पड़ोसी देशों के लिए कहा है कि हमारे साथ रहोगे तो फायदा होगा वरना खामियाजा भुगतना होगा। जयशंकर विदेश मंत्री बनने से पहले भी लंबे समय तक विदेश सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लेकिन उनकी यह भाषा कूटनीतिक नहीं है बल्कि शुद्ध रूप से बदतमीजी और बड़बोलेपन की भाषा है, जो कि भाजपा के प्रवक्ता अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किया था। अफगानिस्तान के खिलाफ हमले की तैयारी करते हुए जॉर्ज बुश ने कहा था कि दुनिया के जो देश अमेरिका के साथ नहीं हैं वे आतंकवादियों के साथ हैं। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। वैसे समय में भी उनके इस बयान की आलोचना हुई थी। लेकिन अभी तो ऐसा कोई समय नहीं है लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो पड़ोसी देश भारत से मिल कर नहीं रहेंगे उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विदेश मंत्री के हिसाब से सिर्फ एक पाकिस्तान है, जो भारत के साथ नहीं है। पता नहीं जयशंकर किस आधार पर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान आदि देशों को भारत के साथ मान रहे हैं? हकीकत यह है कि ये सारे देश भी चीन के असर में हैं और कम या ज्यादा भारत विरोधी रुख अख्तियार कर चुके हैं। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बार-बार पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों के बंडल मिलने के मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? पिछले दिनों कार्मिक, विधि और न्याय मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक में भी सदस्यों ने विधि सचिव से जानना चाहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? सवाल है कि क्या किसी को पता नहीं है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई? या सबको पता है फिर भी मुद्दे को बनाए रखने के लिए बार-बार यह सवाल पूछा जा रहा है? यह सामान्य ज्ञान की बात है कि 1991 में जस्टिस के. वीरास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत जजों को एफआईआर से संरक्षण देते हुए कहा था कि किसी कार्यरत जज के खिलाफ एफआईआर से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इसका मकसद यह था कि जजों को भयमुक्त होकर काम करने का माहौल उपलब्ध कराया जाए। सामान्य ज्ञान की यह बात सबको पता होगी, इसीलिए जस्टिस वर्मा के मामले में जस्टिस वीरास्वामी फैसले की समीक्षा की भी बात कही जा रही है। पिछले दिनों जस्टिस वर्मा के खिलाफ बनी तीन सदस्यों की जांच समिति की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें जजों की पूछताछ में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नकदी मिलने की खबर सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को और उसके बाद चीफ जस्टिस को दी गई थी। सवाल है कि पुलिस को क्यों नहीं नियम के मुताबिक काम करने, नकदी जब्त करने और पंचनामा करने का आदेश दिया गया? इस साल आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं। पहले आपातकाल की बरसी को लोकतंत्र के लिए काला दिन कहा जाता था। आपातकाल के दौरान हुई सरकारी ज्यादतियों की कहानियां दोहराई जाती थीं, लेकिन इस बार %संविधान हत्या दिवस' का जुमला ज्यादा सुनाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार यह जुमला दोहराया। पहले सरकार का इरादा इस मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाने का था, लेकिन कांग्रेस ने उसको पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया तो सरकार पीछे हट गई। उसे लगा कि अगर विशेष सत्र बुलाया तो इन मुद्दों पर भी चर्चा की मांग उठेगी और अगर चर्चा नहीं होने दी तो आपातकाल का नैरेटिव प्रभावित होगा। बहरहाल, सवाल है कि इस साल संविधान हत्या दिवस' का जुमला क्यों बोला गया? इसका कारण कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान बचाओ अभियान शुरू किया। वे हर जगह अपने हाथ में संविधान लेकर जाते हैं और जनसभा करते हैं। इस अभियान को जय बापू, जय भीम, जय संविधान' का नाम दिया गया है। कांग्रेस व दूसरी विपक्षी पार्टियां दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को इस नाम पर एकजुट कर रही हैं। विपक्ष के इस अभियान को पंक्चर करने के लिए संविधान हत्या दिवस' का शोर मचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी और अब वह संविधान बचाने का ड्रामा कर रही है। इससे कांग्रेस के साथ उन पार्टियों की साख पर भी सवाल उठाया जा रहा है, जो आपातकाल के समय कांग्रेस के खिलाफ थीं। दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक दिन में सड़कों के 3,433 गड्ढे भरने का रिकॉर्ड बनाया! इस खबर को क्या कहेंगे? सरकार के पास विजन की कमी या राजधानी दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने की सोच? ऐसा नहीं है कि सरकार ने चुपचाप गड्ढे भर दिए। इसका बड़ा शोरशराबा रहा। इसके लिए दिल्ली के लोकनिर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा खुद फावड़ा आदि लेकर सड़क पर उतरे। गड्ढे भरे जाते समय पूजा-पाठ आदि भी हुआ जैसे किसी परियोजना का भूमि पूजन होता है। कई दिन पहले से दिल्ली के अखबारों में इसकी खबरें छपवाई गईं। 24 जून को जब गड्ढे भरने का यह अभियान चल रहा था तो दिल्ली में चारों तरफ इसे देखा जा सकता था। गली, मोहल्लों में भी ऐसे गड्ढे खोज-खोज कर भर दिए गए और रिकॉर्ड बनाने का ऐलान कर दिया गया। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछले चार महीने में यह संभवतः सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो काम रुटीन में होता है और चुपचाप चलता रहता है उसको अगर सरकार उपलब्धि बता कर या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने लायक रिकॉर्ड बता रही है तो अंदाजा लगाइए कि अगर उसने नई सड़क बनाई या फ्लाईओवर वगैरह बनाया तो क्या होगा? यह पता नहीं चल सका कि किसी जीनियस के दिमाग में यह आइडिया आया था, किसी नेता ने यह सुझाव दिया या किसी अधिकारी ने मजे लेने और मजाक बनवाने के लिए यह आइडिया दिया, जिस दिल्ली सरकार ने गंभीरता से अमल किया? चुनाव आयोग 15 सितंबर के बाद किसी भी समय बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा कर सकता है। बताया जा रहा है कि उससे पहले यानी अगले ढाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 या 10 बार बिहार का दौरा करेंगे। बिहार के हर डिवीजन यानी संभाग में प्रधानमंत्री की एक सभा होगी। गौरतलब है कि बिहार में नौ संभाग हैं। हर दौरे में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और उनकी जनसभा होगी। पिछली यात्रा में सीवान में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उससे पहले बिहार दौरे में उन्होंने पटना हवाईअड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और बिक्रमगंज में जनसभा की थी। बताया जा रहा है कि अगस्त में किसी दौरे में पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन होगा। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने बिहार चुनाव को प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ने का फैसला किया है। गौरतलब है कि भाजपा ने साफ कर दिया है कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आगे के सभी दौरों के लिए केंद्रीय मंत्री और जनता दल (यू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को समन्वयक बनाया गया है। वैसे भी प्रधानमंत्री की पिछली सभाओं में भी भीड़ जुटाने का काम जनता दल (यू) के नेताओं ने ही किया है और आगे भी वे ही करेंगे। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा भाजपा और अकाली दल की राजनीति

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सायं पीपलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/33862)

साहिब बानो बनी खुशी तिवारी.... प्रॉपर्टी के लिए की शादी और फिर हत्या

कुशीनगर।

प्रॉपर्टी के लिए झूठी शादी कर हत्या का खेल करने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा घटना का खुलासा करते हुए बताया गया पिछले 6 जून को थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के अंतर्गत सुकरौली मझना नाला के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा पंजीकृत करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार, और क्षेत्राधिकारी कसया कुंदन सिंह के नेतृत्व में जांच टीमें में बनाकर जांच प्रारंभ कर दी गई थी। शव की पहचान इंद्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामदयाल तिवारी निवासी पड़खर (स्टिठौला) थाना मझौली,जनपद जबलपुर,मध्य प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस टीम मध्य प्रदेश जबलपुर पहुंची तो पता चला कि 3 जून को इंद्र तिवारी गोरखपुर स्थित किसी खुशी तिवारी के साथ शादी करने के लिए निकले हुए थे। इस संदर्भ में पुलिस ने कूट रचित आधार कार्ड खुशी तिवारी की गिरफ्तारी करते हुए पूछताछ की तो पता चला उसका असली नाम साहिब बानो पुत्री अनवर अली निवासी मीठा बेल, थाना झगहा, जनपद गोरखपुर है। और फिर जो असलियत निकलकर सामने आई वह हैरान करने वाली थी। खुशी तिवारी उर्फ साहिब बानो कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया से कौशल कुमार गौड़ पुत्र किशुन गौड निवासी सोंडा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया जिनका हाल मुकाम गोरखपुर था के संपर्क में आई थी। और वह दोनों गोरखपुर में एक साथ बतौर पति-पत्नी एक किराए के मकान में रह रहे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर इंद्र कुमार तिवारी उम्र 45 वर्ष का एक वायरल वीडियो देखा जिसमें वह अपनी शादी न होने की व्यथा एक धर्म गुरु के सामने कर रहे थे और अपनी 18 एकड़ जमीन का

भी जिक्र कर रहे थे। साहिब बानो ने कौशल कुमार के साथ मिलकर योजना बनाई और इंद्र कुमार तिवारी से फर्जी शादी कर उसकी संपत्ति हड़पने का साजिश रचने लगी। साजिश के अनुसार संदीप तिवारी उर्फ कौशल कुमार इंद्र कुमार तिवारी से मिलने जबलपुर पहुंचा और उसने अपनी बहन खुशी तिवारी का जिक्र करते हुए उससे शादी करने का प्रस्ताव किया। इसके बाद साहिब बानो उर्फ खुशी तिवारी से लगातार फोन से इंद्र कुमार तिवारी से बातचीत होती रही और खुशी तिवारी उर्फ साहिब बानो शादी करने के लिए इंद्र कुमार तिवारी को गोरखपुर बुलाई।

शादी करने के लिए कौशल इंद्र कुमार तिवारी को 3 जून को साहिब के कमरे पर पहुंचा फिर साहिब इंद्र कुमार तिवारी और कौशल कुमार के साथ कमरे पर रहने लगी। साहिब बानो और कौशल ने इंद्र कुमार तिवारी से एक हलफनामा बनवाया जिसके अनुसार उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी तथा अपने रिश्तेदार कौशल उर्फ संदीप को वारिस घोषित करते हुए हस्ताक्षर किए।

साहिब बानो और कौशल ने शमसुद्दीन की मदद से हत्या की साजिश रची और 5 जून को इंद्र कुमार तिवारी को अपने साथ कुशीनगर स्थित आइडियल होटल लेकर आए। शादी का झूठा नाटक करते हुए होटल के कमरे में सिंदूर लगाकर झूठी शादी की और इसका वीडियो भी बनाया। अभियुक्त ने इंद्र तिवारी को पनीर राइस में नींद की गोलियां अल्प्रेक्स 5 टैबलेट मिलाकर दी जिससे वह अचेत हो गया। योजना के तहत तीनों अभियुक्तों ने इंद्र तिवारी को गाड़ी से घटनास्थल सुकरौली पर ले जाकर अचेत अवस्था में चाकू से वार कर हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया तथा ज्वेलरी और पैसे लेकर चले गए। इस प्रकार प्रॉपर्टी के लिए अपनी पहचान और धर्म बदलकर साहिब बानो ने अपने बॉयफ्रेंड कौशल उर्फ संदीप तथा सहयोगी शमसुद्दीन के साथ मिलकर इंद्र तिवारी की हत्या कर डाली। पुलिस ने मृतक का मोबाइल, उसका आधार कार्ड,एटीएम कार्ड, मृतक के जमीन की खसरा खतौनी और शादी के लिए ले गए जेवरात सहित घटना में प्रयुक्त कार यूपी 53 BJ 61 29 भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान थाना कोतवाली हाटा, प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह स्वाट टीम, निरीक्षक अमित शर्मा स्वाट टीम, उप निरीक्षक चंद्र भूषण पांडे चौकी प्रभारी सुकरौली, उप निरीक्षक आलोक कुमार स्वाट टीम , उप निरीक्षक संत राज यादव सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक श्री मित्रा ने सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25000 का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है।

अभिनय कार्यशाला के समापन अवसर पर नाट्य मंचन देख भावुक हुए दर्शक

समर्पण, मेहनत बल पर अभिनय के क्षेत्र में बना सकते हैं कैरियर : रजनीकांत मणि

कसया, कुशीनगर।

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी संस्कृति विभाग के द्वारा सहयोग वेलफेयर सोसायटी के सहयोग से बुद्ध स्नातकोत्तर महा विद्यालय के भंते सभागार में आयोजित बीस दिवसीय अभिनय कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रतिभागियों नाट्य मंचन को देखकर दर्शक भावुक हो गए। रविवार को अभिनय कार्यशाला के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि कला, संगीत और नाट्य ये तीनों ऐसे क्षेत्र है। जो न केवल मनोरंजन के माध्यम है बल्कि इनमें शानदार कैरियर भी मौजूद है। पहले यह शौक का विषय था लेकिन वर्तमान में यह पूर्ण कालिक कैरियर बन चुका है। अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति में इस क्षेत्र में समर्पण भाव से मेहनत करने की इच्छा हो तो आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं है। विशिष्ट अतिथि डॉ निगम मौर्य, सुनील कुमार, अमरेंद्र नारायण सिंह ने अपने विचार रखे। विशेष प्रशिक्षक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं हास्य कलाकार सी पी भट्ट उर्फ ढेला बाबा के निर्देशन में प्रतिभागियों ने लघु नाटक युद्ध नहीं शांति नाटक का मंचन किया। जिसमें परिवार के एक व्यक्ति के मरने पर उससे जुड़े रिश्तों तक कैसे दु:ख पहुंचता है। बखूबी कलाकारों ने चित्रण किया। जिसे देख सभी भावुक हो गए। नाटक के माध्यम से विश्व शांति, जात पात को दूर कर सामाजिक समरता, एकता का आह्वान किया गया। मुख्य प्रशिक्षक फिल्म अभिनेता एवं वरिष्ठ रंगकर्मी अजय त्रिपाठी ने कार्यशाला के महत्व, अनुशासन, समय के पालन और योग के बारे में बताया। सहयोग के लिए महा विद्यालय प्राचार्य विनोद मोहन मिश्रा के प्रति आभार जताया गया। इस दौरान श्वेता पटेल, आस्था भारती, सिकंदर चौहान, आराध्य तिवारी, मंगलम शर्मा, अंश, विनोद बर्नवाल, ममता गुप्ता, आँचल सिंह, अंजलि पांडे उर्फ रोबोट, वादन रवि शंकर पाठक सहित प्रतिभागी मौजूद रहे।

नगर पालिका अध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

पडरौना, कुशीनगर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम -मन की बात के 123वें संस्करण का सजीव प्रसारण आज नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल के आवास पर कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में उत्साहपूर्वक सुना गया। जैसे ही कार्यक्रम आरंभ हुआ, समूचा परिसर राष्ट्रभक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश की विविध उपलब्धियों, जनभागीदारी से हुए सामाजिक बदलावों, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, युवाओं की भूमिका और नवाचार पर केंद्रित प्रेरणादायक बातें साझा कीं। पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, भगवान जगन्नाथ यात्रा, सामाजिक सुरक्षा, इमरजेंसी के 50 वर्ष, बोडोलैंड के युवाओं का मुख्यधारा में लौटना, महिला सशक्तिकरण, भगवान बुद्ध के विचारों का प्रसार, और जीवन में डॉक्टरों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने देशवासियों को सशक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री की वाणी में देश के लिए समर्पण और जन-जन की भागीदारी का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री जायसवाल ने कहा कि -मन की बात- केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश को दिशा देने वाला संवाद है। यह समाज के हर वर्ग को जोड़ता है और देश के कोने-कोने में हो रहे सकारात्मक कार्यों को राष्ट्रीय पटल पर लाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाएं और प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में सेवा और विकास का कार्य करें। कार्यक्रम के पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम ने न केवल एकजुटता का संदेश दिया, बल्कि कार्यकर्ताओं को देश सेवा के प्रति और अधिक प्रेरित किया। इस दौरान प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल के अलावा निरंजन शर्मा गौरव रौनियार भागवत प्रसाद राजेश जायसवाल मनीष सिंह बाबूलाल साह अंकित अग्रवाल राजू साह राहुल सिंह मदन चौधरी अभय मद्धेशिया संजय साह रवि शर्मा आदर्श जायसवाल केदार मद्धेशिया विपिन जायसवाल बबलू शर्मा पिंटू साह हरेंद्र गुप्ता सन्तोष चौहान अरुण गुप्ता सहित अन्य उपस्थित रहे।

ग्यारह हजार विद्युत की चपेट में आने से प्राइवेट लाइनमैन की मौत

मठुडीह,कुशीनगर । कसया तहसील के ग्राम सभा कुड़वा दिलीपनगर के फुलवापट्टी में रविवार को विद्युत फाल्ट ठीक कर रहे एक प्राइवेट लाइनमैन की 11 हजार लाइन की चपेट में आकर मृत्यु हो गई।मौके पर पहुंचे परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा किया।थाना प्रभारी ओमप्रकाश तिवारी ने दोषियों पर कार्रवाई का अस्वाशन दिया तब परिजन शव को पीएम को तैयार हुए।कसया थाने के धुरिया गांव निवासी 35 वर्षीय अमित तिवारी विगत तीन वर्षों से प्राइवेट लाइनमैन का कार्य करते थे। रविवार को दोपहर वे फुलवापट्टी गाव के ट्रांसफार्मर के पास फाल्ट ठीक कर रहे थे। इसी दौरान वे विद्युत चपेट में आये और ट्रांसफार्मर से नीचे गिरे और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार्य के दौरान विद्युत आपूर्ति होने से दुर्घटना हुई।

50 हजार का इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त देवरिया में गिरफ्तार

एसटीएफ प्रयागराज व रामपुर कारखाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

देवरिया।

गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित और शातिर अपराधी तैयब को शनिवार को थाना रामपुर कारखाना पुलिस और एसटीएफ प्रयागराज की संयुक्त टीम ने पटनवा पुल के पास से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। अभियुक्त आजमगढ़ जनपद के थाना रौनापार अंतर्गत हिनहई गुलौगढ़ का निवासी है, जो वर्ष 2020 से फरार चल रहा था। तैयब के खिलाफ देवरिया, वाराणसी और आजमगढ़ में गोवध, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एससी/एसटी एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराधों में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे (मुअसं-887/2020) में यह वांछित था, जिस पर पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी एसपी विक्रान्त वीर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई। एएसपी उत्तरी अरविंद कुमार वर्मा और सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी के पर्यवेक्षण में चली इस कार्रवाई में एसटीएफ प्रयागराज व रामपुर कारखाना पुलिस की भूमिका सराहनीय रही।अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

छितौनी सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटा, व्यापारियों और राहगीरों को राहत

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। छितौनी नगर पंचायत के बुलहवापुरी वार्ड की सब्जी मंडी में रविवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई 24 लाख रुपये की लागत से बन रही सीसी रोड के निर्माण के दौरान की गई। सब्जी मंडी में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने बांस और पाइप गाड़कर अतिक्रमण कर रखा था। इससे राहगीरों और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। नगर प्रशासन ने मंडी को विस्तार देने के लिए इन अवैध कब्जों को हटाया। नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक निषाद ने कहा कि यह कदम लोगों की सुविधा के लिए जरूरी था। उन्होंने बताया कि निर्माण के बाद खाली जगह पर लोग अतिक्रमण कर लेते, जिससे भविष्य में समस्याएं बढ़तीं। इस कार्रवाई का सभासद विजय कुमार गुप्ता, रमेश कुमार और राजेश साहनी सहित अन्य पार्षदों ने समर्थन किया। स्थानीय लोगों ने भी नगर पंचायत अध्यक्ष की सराहना की।अतिक्रमण हटने से सब्जी मंडी में राहगीरों का आवागमन आसान हो गया है। मंडी को मिली अतिरिक्त जगह से व्यापारिक गतिविधियां बेहतर होंगी।

श्रृंगार प्रतिष्ठान का ब्लॉक प्रमुख ने किया उद्घाटन

कप्तानगंज कुशीनगर) । कप्तानगंज के वार्ड 17 स्थित मां स्वर्गीय सुदामा देवी काम्प्लेक्स में सृष्टि श्रृंगार प्रसाधन का उद्घाटन शनिवार को रामकोला ब्लाक प्रमुख दिग्विजय सिंह उर्फ लक्ष्मण ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठान कस्बे के बीच होने से ग्राहकों की भीड़ होगी। इसके अलावा महिलाओं के समस्त सामग्री भी उपलब्ध होने से दुकान की एक प्रमुखता है. इस मौके पर पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ किसान नेता राधेश्याम सिंह, विजय यादव, कॉम्प्लेक्स के प्रो बेचू बीए, रमेश जैसवाल, इमदाद हुसैन , फिरोज अहमद, कन्हिया यादव, पिंटू यादव, प्रतिष्ठान के प्रो.कन्हिया लाल सोनी, सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

नहर में डूबी कार से मिला शहजाद का शव

नेबुआ नौरंगिया,कुशीनगर ।

नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बवपरना गांव के पास शनिवार रात बड़ी गंडक नहर से एक डूबी हुई लग्जरी कार बाहर निकाली गई। कार के अंदर ड्राइवर सीट और पीछे की ओर फंसा हुआ शव मिला, जिसकी पहचान पकड़ियार गांव के रहने वाले 35 वर्षीय शहजाद सिद्दिकी के रूप में हुई।शहजाद 10 दिन पहले ही सऊदी अरब से घर लौटा था। गुरुवार शाम घर से निकला था, पर लौटकर नहीं आया। परिजनों ने पहले तो सोचा कि वह ससुराल में है, लेकिन जब शुक्रवार भी गुजर गया और शनिवार की सुबह तक कोई जानकारी नहीं मिली, तो चिंता बढ़ गई।झाड़ियों में दिखा नंबर प्लेट, नहर में मिली कार के पार्ट्स,शनिवार सुबह राहगीरों को बवपरना के पास गंडक नहर की पटरियों पर झाड़ियों के बीच कुछ चमकता हुआ नजर आया। पास जाकर देखा तो एक टूटी हुई नंबर प्लेट थी।

नहर में झांकने पर कुछ लोहे के टुकड़े भी नजर आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नंबर प्लेट की जांच की तो पता चला कि यह गाड़ी शहजाद के नाम रजिस्टर्ड है नंबर यूपी15ए0010चालक शहजाद सिद्दिकी, चालक शहजाद सिद्दिकी, इसके बाद थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। SDRF के जवानों और मदनपुर-शुकौली क्षेत्र के चार अनुभवी मछुआरों की मदद से लगभग 13 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ।

सीट में फंसा मिला शव, बचने की कोशिश नाकाम रही

जब कार को जेसीबी से बाहर निकाला गया, तो उसमें शहजाद का शव सीट छोड़कर बाईं और पीछे की तरफ फंसा हुआ मिला। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि डूबते वक्त उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया।सदर एसडीएम व्यास राव उमराव और थाना प्रभारी मौके पर देर रात तक डटे रहे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। घर से निकला था यह कहकर- ससुराल जा रहा हूं परिजनों के मुताबिक, गुरुवार शाम शहजाद के मोबाइल पर किसी का फोन आया। वह जल्दबाजी में यह कहकर निकला कि ससुराल जा रहा हूं और अपनी कार में बैठकर निकल गया। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि विदेश से लौटने के बाद शहजाद घर में किसी बात को लेकर नाराज था। कुछ लोगों को आशंका है कि यह हादसा नहीं, बल्कि आत्महत्या हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी जांच के सभी एंगल पर काम कर रही है।

डॉ0 सीमांत कुमार वर्मा को बनें नेबुआ नौरंगिया सीएचसी प्रभारी

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया विकास खण्ड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली लापरवाही, अनियमितता और अव्यवस्था पर आखिरकार प्रशासन का धैर्य जवाब दे गया। लगातार मिल रही गंभीर शिकायतों और जनप्रतिनिधियों के दबाव के बीच जिलाधिकारी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए तत्काल प्रभाव से सीएचसी प्रभारी डॉ0 रजनीश श्रीवास्तव को पद से हटा दिया। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर ने जिलाधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 23 जून को डॉ0 रजनीश श्रीवास्तव को हटाकर वहां तैनात डॉ0 सीमांत कुमार वर्मा को प्रभारी नियुक्त कर दिया। यह कदम स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त लापरवाही के खिलाफ प्रशासन की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दर्शाता है। भाजपा पदाधिकारियों का आरोप था कि अस्पताल पूरी तरह बदहाल है। डॉक्टर नियमित रूप से ड्यूटी पर नहीं आते, मरीजों को इलाज किये बगैर ही रेफर कर दिया जाता है और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में घोर लापरवाही बरती जाती है। यही नहीं अस्पताल परिसर गंदगी का अड्डा बना हुआ है और आवश्यक दवाएं तक उपलब्ध नहीं होतीं।नौरंगिया मंडल अध्यक्ष सूरज गोविन्द राव, बगही मंडल अध्यक्ष सर्वजीत गुप्ता और भुजौली मंडल अध्यक्ष सहित भाजपा के दर्जनों स्थानीय पदाधिकारियों ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन होगा। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि जनता को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एक नजर

भारत गौरव ट्रेन से दक्षिण भारत की दिव्य यात्रा

गोरखपुर । दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करने के उद्देश्य से चर्चित भारत गौरव एक्सप्रेस चलने का फैसला लिया गया है जो बिहार और झारखंड सहित अनेक राज्यों के लोगों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों तक ले जाएगी। भागलपुर स्टेशन से इस भारत गौरव एक्सप्रेस की शुरुआत होगी और 12 दिवसीय यात्रा के तहत यात्रियों को तिरुपति, रामेश्वर, -मदुरई-, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन के दर्शन करवायेगी । आईआरसीटीसी की इस विशेष पर्यटक ट्रेन के द्वारा भक्तों को दक्षिण भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों और पवित्र स्थानों पर दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इस ट्रेन में भागलपुर, जसीडिह, मधुपुर, बराकर, धनबाद, बोकारो, मुरी, रांची, राउरकेला, झारसुगुडा, चाम्पा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग सहित कई बोर्डिंग और डिबोर्डिंग पॉइंट शामिल हैं। इस भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर क्लास (इकोनॉमी) की 640 सीटों की व्यवस्था की गई है जबकि तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में 70 सीटें हैं। भारत गौरव यात्रा की टिकट लेने वाले यात्रियों को रेल यात्रा के साथ-साथ सड़क यात्रा, भोजन (चाय, नाश्ता, लंच, डिनर), डबल/ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर आरामदायक और साफ आवास (इकोनॉमी के लिए नॉन-एसी; स्टैंडर्ड और कम्फर्ट क्लास के लिए एसी),बसों द्वारा स्थानांतरण और दर्शनीय स्थलों की यात्रा, ऑनबोर्ड टूर एस्कॉर्ट, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह यात्रा आराम और सुरक्षा के साथ कई तीर्थों के दर्शन और आध्यात्मिक पूर्ति प्राप्त करने का एक अद्वितीय मौका प्रदान करती है - वो भी किफायती कीमत पर। बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के जो लोग इस यात्रा के भागीदार बनना चाहते हैं वह IRCTC के कोलकाता और रांची कार्यालय या अधिकृत एजेंटों) के माध्यम से भी बुकिंग कर सकते हैं।

ऋषि कश्यप की वंशकथाओं में छिपा है सृष्टि का रहस्य - वागीश मणि त्रिपाठी

श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धा और भक्ति का रहा चरमोत्कर्ष

भटनी देवरिया।

क्षेत्र के मिश्रौली दीक्षित गांव में आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण हर हर महादेव व जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। कथा वाचक पंडित वागीश मणि त्रिपाठी ने ऋषि कश्यप की पत्नियों और उनसे उत्पन्न विविध जीवों की विस्तृत पौराणिक कथाओं के माध्यम से सृष्टि की गूढ़ रचना का रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया, जिनमें अदिति, दिति, दनु, कद्रू, विनता, सुरसा प्रमुख थीं। इनसे देवता, दैत्य, दानव, नाग, गरुड़, अरुण जैसी अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई। यह समस्त सृष्टि एक विराट ब्रह्म योजना का हिस्सा है, जिसमें हर जीव का विशेष महत्त्व और उद्देश्य है। कथा के अगले प्रसंग में सती और भगवान शंकर की कथा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव को आमंत्रित न करने पर सती ने आत्माहुति दे दी। यह प्रसंग श्रोताओं को अत्यंत भावुक कर गया। इसके बाद भगवान शिव का तांडव, वीरभद्र का प्राकट्य और दक्ष यज्ञ का विध्वंस भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। कथा स्थल पर श्रद्धालु देर शाम तक जुटे रहे। इस दौरान विनोद दीक्षित, महेंद्र दीक्षित, भगवान दीक्षित, सुमन्त दीक्षित, हरिशंकर दीक्षित, अजय दीक्षित उर्फ रिंकू, भगवती यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

मोहर्रम को लेकर एसपी विक्रान्त वीर ने किया पैदल गश्त, सुरक्षा के प्रति जताई कड़ी प्रतिबद्धता

देवरिया। त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने शहर के प्रमुख मार्गों पर थाना कोतवाली पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा तैयारियों का भौतिक निरीक्षण किया। गश्त का उद्देश्य न केवल संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति दर्ज कराना था, बल्कि आम जनता में सुरक्षा का विश्वास भी कायम करना था। सुभाष चौक, सिविल लाइन, कचहरी चौराहा, रोडवेज, ताजिया जुलूस मार्गों एवं अन्य संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण करते हुए एसपी ने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों एवं धर्मगुरुओं से संवाद कर आपसी समन्वय बनाए रखने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी अफवाह या विवाद की स्थिति में पुलिस तत्काल सख्त कार्रवाई करेगी। थाना कोतवाली प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह को निर्देशित किया गया कि चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए और सोशल मीडिया की निगरानी लगातार की जाए ताकि कोई भ्रामक या सांप्रदायिक सामग्री फैलने से पहले ही रोकी जा सके। इस पैदल गश्त के दौरान एसपी विक्रान्त वीर ने रोडवेज बस स्टेशन पर वाहनों की चेकिंग भी कराई। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के साथ मिलकर उन्होंने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने व गति सीमा का पालन करने की सख्त हिदायत दी। गश्त के दौरान एसपी के पीआरओ डॉ महेन्द्र कुमार सहित पुलिस टीम मौजूद रही। एसपी ने दो टूक कहा कि मोहर्रम जैसे संवेदनशील पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है, और इसके लिए हर आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि की सूचना तुरंत 112 या नजदीकी थाने में दें।

विनिर्माण की मजबूती के लिए प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क जरूरी, कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट

नई दिल्ली । भारत में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी की जरूरत है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड की नई रिपोर्ट एलेवेटिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग रेजिलिएंस चार्टिंग द पाथ टू सेल्फ-रिलायंस में यह जानकारी दी गई है। यह रिपोर्ट भारत के विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के 94 वरिष्ठ निर्णयकर्ताओं के सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें बड़े उद्योगों से लेकर एमएसएमई तक का दृष्टिकोण शामिल है। प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क का मतलब है सभी सुविधाओं से लैस होना। जहां आवश्यक बुनियादी ढांचे, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, और कनेक्टिविटी, पहले से ही मौजूद होते हैं। व्यवसायों को बिना किसी देरी के तुरंत अपने परिचालन शुरू करने की अनुमति मिलती है, जिससे निर्माण और रखरखाव में लगने वाले समय और लागत में कमी आती है। कुशमैन एंड वेकफील्ड के मुंबई और न्यू बिजनेस के कार्यकारी प्रबंध निदेशक गौतम सराफ ने कहा कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमारी रिपोर्ट में यह सामने आया कि बुनियादी ढांचे में निवेश, स्पष्ट नीतियां और उद्योग की मंशा, मजबूती से जुड़े हैं। सर्वे के अनुसार 88 प्रतिशत निर्माता बुनियादी ढांचे में सुधार के चलते अपने संचालन का विस्तार कर रहे हैं और 95 प्रतिशत ने अधिक से सरकार समर्थित कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक्स पहुंच की सूचना दी है। हालांकि, सराफ ने यह भी कहा कि भारत को लॉजिस्टिक्स लागत, एकीकृत सुविधाओं की कमी और एमएसएमई की उत्पादकता में

महंगी लागत और क्षमता अंतराल को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और बेहतर भूमि अधिग्रहण तंत्र केवल सहायक साधन नहीं है, बल्कि नीति को उत्पादन क्षमता में बदलने के लिए अनिवार्य तंत्र है। रिपोर्ट में भारत की विनिर्माण वृद्धि को बाधित करने वाली चार प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, वैश्विक बेंचमार्क से पीछे चल रही वेयरहाउसिंग क्षमता, कम मूल्य संवर्धन और कौशल की कमी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट ने पांच- आयामी रणनीति तैयार की।

प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स के विकास में तेजी।
एमएसएमई की परिभाषा का पुनर्मूल्यांकन।
मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की तेजी से शुरुआत
लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम में निवेश।
एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रोत्साहनों के जरिए एमएसएमई निर्यात को सशक्त बनाना।

प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का महत्व बढ़ रहा है

कुशमैन एंड वेकफील्ड में लॉजिस्टिक्स व इंडस्ट्रियल सर्विसेज इंडिया के प्रबंध निदेशक अभिषेक भूटानी ने कहा कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो नीतिगत समर्थन और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण तीव्र वृद्धि के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे शोध से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला है कि प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का महत्व बढ़ रहा है। ये पूर्व-स्वीकृत बुनियादी ढांचे के लिए, तैयार क्षेत्र बाजार में आने के समय को कम करने, अग्रिम पूंजीगत व्यय को कम करने और परिचालन जोखिमों को कम करने में मदद कर रहे हैं, खासकर एमएसएमई के लिए जो विस्तार करना चाहते हैं। भूटानी ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे कंपनियां नए क्षेत्रों में विस्तार कर रही हैं, उनके लिए लॉजिस्टिक्स, कुशल प्रतिभा और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से युक्त ऐसे टर्नकी इकोसिस्टम की उपलब्धता निर्णायक साबित होगी।

बांग्लादेश ने अडाणी की पावर को दिए 3200 करोड़ रुपये, अभी भी बाकी हैं 4200 करोड़

नई दिल्ली। बांग्लादेश ने जून में बिजली आपूर्ति समझौते के तहत गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी पावर को 384 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। इतना भुगतान करने के बाद बांग्लादेश ने अडाणी पावर को देने वाले बकाया राशि को और कम कर दिया है। इस भुगतान के साथ, बांग्लादेश ने अडाणी पावर का लगभग 2 बिलियन डॉलर की कुल बिल राशि में से लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का निपटान कर दिया है। अभी भी उसे अडाणी पावर को 500 मिलियन डॉलर देने होंगे। अभी पूरी तरह से उसका बकाया खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष कोयले की लागत और संयंत्र क्षमता गणना से जुड़े कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश के 384 बिलियन डॉलर का पेमेंट करने के बाद भारतीय कंपनी के साथ बिजली आपूर्ति समझौते के तहत बकाया राशि में उल्लेखनीय कमी आई।

अडानी ने कथित तौर पर जनवरी-जून अवधि के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ करने पर सहमति व्यक्त की है, जो लगभग 20 मिलियन डॉलर है। बशर्ते बांग्लादेश अपनी भुगतान प्रतिबद्धता बनाए रखे। यानी अगर बांग्लादेश को बिजली चाहिए तो उसे समय-समय पर अपने बिलों का भुगतान करते रहने होगा। इसी शर्त पर अडाणी समूह ने लेट पेमेंट सरचार्ज पर छूट की सहमति व्यक्त की है। अडाणी पावर और बांग्लादेश के बीच साल 2017 में बिजली समझौता हुआ था। इस समय शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी। पिछले साल उनके सत्ता से दखल होने के बाद बिजली आपूर्ति सौदे की जांच शुरू हुई। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बिजली खरीद समझौते की फिर से जांच करने के लिए ऊर्जा और कानूनी विशेषज्ञों वाली एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की बात कही थी। साल 2017 में हुए समझौते के तहत झारखंड में अडाणी पावर के गोड्डा बिजली प्लांट को कोयले से उत्पन्न 100 प्रतिशत बिजली 25 वर्षों की अवधि के लिए बांग्लादेश को देनी थी। लेकिन बांग्लादेश की ओर भुगतान में की गई देरी की वजह से नवंबर 2024 में अडाणी पावर ने बिजली सप्लाई रोक दी थी। क्योंकि मोहम्मद यूनुस के देश के ऊपर बहुत ज्यादा देनदारी हो गई थी। कुछ देनदारी देने के बाद अडाणी पावर ने मार्च 2025 में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी।

बढ़त के साथ बंद हुआ था बाजार, कैसी रहेगी निफ्टी की चाल

नई दिल्ली।

23 जनवरी से शुरू हुए 27 जून तक हुए ट्रेडिंग में इस हफ्ते बाजार की शुरुआत स्थिर रही। लेकिन निफ्टी ने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ी है। और 25,300 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के स्तर को पार कर लिया। इतना ही नहीं सप्ताह के अंत में NIFTY ने 2फीसदी से अधिक की बढ़त हासिल की और 25,650 के करीब नया हाई स्तर बनाया। वैश्विक स्तर पर ईरान और इजरायल के बीच हुए संघर्ष विराम के चलते वैश्विक बाजारों में उत्साह बढ़ा, जिसने भारतीय शेयर बाजार में आई इस तेजी को समर्थन दिया। इस तेजी की वजह से NIFTY SMALLCAP 100 में 4 फीसदी और MIDCAP 100 में 2फीसदी से अधिक की बढ़त हुई। यह बढ़त निवेशकों के बढ़ते जोखिम लेने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगले हफ्ते निफ्टी की चाल कैसी रहेगी? आइए ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से जानते हैं। आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल के अनुसार अगर निफ्टी फिफ्टी में 25,300 के ऊपर यह ब्रेकआउट एक महीने की स्थिरता के बाद आया है। यह साफ तौर पर बाजार के मूड में बदलाव का संकेत दे रहा है। इसलिए, हमारा पहले का सतर्क या नकारात्मक दृष्टिकोण फिलहाल रुका हुआ है। जिगर एस पटेल के अनुसार आगे देखें तो 25,700-25,900 का क्षेत्र तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इस रेंज के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट नई तेजी का रास्ता खोल सकता है। लेकिन अगर NIFTY 25,300 के स्तर के नीचे बंद होता है तो यह ब्रेकआउट असफल माना जाएगा। यह स्तर इसका सपोर्ट माना जाएगा। ऐसे समय में निवेशकों को सतर्क रणनीति अपनाने की जरूरत हो सकती है।

एक नजर

मई 2025 में सीमेंट उद्योग ने पकड़ी रफ्तार; खपत 9 प्रतिशत बढ़ी, कीमतों में 8 फीसदी का उछाल

नई दिल्ली । सीमेंट उद्योग में मई 2025 में सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट की खपत 39.6 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) हो गई है, जबकि औसत सीमेंट कीमतों में भी करीब 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें बताया गया कि कम बिक्री के बाद भी सीमेंट उद्योग ने मई 2025 में 50 किलोग्राम बैग की कीमत 8 प्रतिशत बढ़कर 360 रुपये रही, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह कीमत 340 रुपये थी। यह साल-दर-साल आधार पर 7फीसदी कम थी। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों (अप्रैल और मई) में कीमतों में 7 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि इनपुट लागत में स्थिरता के कारण परिचालन मार्जिन में भी सुधार हुआ है। इसका कारण कोयले और पेटकोक की ऊर्जा कीमतें कम है तथा डीजल की कीमतें स्थिर है। वहीं, अप्रैल और मई 2025 में कुल बिक्री वॉल्यूम 8 प्रतिशत बढ़कर 78.7 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जबकि पूरे FY2025 में यह आंकड़ा 6.3 फीसदी की वृद्धि के साथ 453 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंचा। आईसीआर को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में सीमेंट की मांग 6 से 7 प्रतिशत बढ़कर 480 से 485 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। इसे आवासीय और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों से निरंतर मांग का समर्थन मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आईसीआर कंपनियों के मार्जिन वित्त वर्ष 2026 में 80 से 150 आधार अंक बढ़कर 16.3फीसदी से 17फीसदी तक पहुंच सकते हैं। ईंधन लागत की बात करें तो जून 2025 में कोयले की कीमतें 19फीसदी घटकर 100 डॉलर प्रति टन और पेटकोक की कीमतें 2फीसदी घटकर 10,880 रुपये प्रति टन हो गई। डीजल की कीमत 88 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रही। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के दौरान कोयले की कीमतों में 6 फीसदी कम थीं, पेटकोक में 1फीसदी की बढ़ोतरी हुई और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। सीमेंट निर्माता संघ (सीएमए) के अनुसार, भारत में सीमेंट उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 690 मीट्रिक टन है।

सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से नौ का बाजार पूंजीकरण 2.34 लाख करोड़ रुपये बढ़ा

नई दिल्ली । सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से नौ के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह कुल मिलाकर 2,34,565.53 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। शेयर बाजार में तेजी के रुख के बीच सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,650.73 अंक या दो प्रतिशत चढ़ गया। शीर्ष 10 कंपनियों में सिर्फ इन्फोसिस के बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई। समीक्षाधीन सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 69,556.91 करोड़ रुपये बढ़कर 20,51,590.51 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। शीर्ष 10 कंपनियों में सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रही। भारती एयरटेल की बाजार हैसियत 51,860.65 करोड़ रुपये बढ़कर 11,56,329.94 करोड़ रुपये पर और एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकन 37,342.73 करोड़ रुपये बढ़कर 15,44,624.52 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 26,037.88 करोड़ रुपये बढ़कर 5,88,213.55 करोड़ रुपये रहा। आईसीआईसीआई बैंक की बाजार हैसियत 24,649.73 करोड़ रुपये बढ़कर 10,43,037.49 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मूल्यांकन 13,250.87 करोड़ रुपये बढ़कर 6,05,523.65 करोड़ रुपये पर और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का 8,389.15 करोड़ रुपये बढ़कर 7,18,788.90 करोड़ रुपये हो गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने सप्ताह के दौरान 3,183.91 करोड़ रुपये जोड़े और इसका बाजार पूंजीकरण बढ़कर 12,45,761.80 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 293.7 करोड़ रुपये बढ़कर 5,41,850.99 करोड़ रुपये हो गया। इस रुख के उलट इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 5,494.8 करोड़ रुपये घटकर 6,68,256.29 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, एलआईसी, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्थान रहा।

भारतीय शेयर बाजार में एफपीआई की जोरदार वापसी, जून में अब तक 8915 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश

नई दिल्ली । विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इस हफ्ते भारतीय इक्विटी बाजार में भारी निवेश किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने 23 जून से 27 जून के सप्ताह के दौरान भारतीय बाजार में 13,107.54 करोड़ रुपये डाले हैं। यह निवेश भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चला कि विदेशी निवेशकों ने खासकर सोमवार और शुक्रवार को बढ़-चढ़कर बाजारों में पैसे डाले। इन नए निवेशों के साथ जून के महीने में कुल शुद्ध निवेश अब 8,915 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों की गतिविधियों में यह बदलाव हाल के दिनों में अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बाद आया है। संघर्ष विराम के बाद वैश्विक बाजार की धारणा में सुधार हुआ है। इससे विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों को अधिक सकारात्मक रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। वैश्विक स्थिरता, नीतिगत समर्थन और मजबूत आर्थिक संकेतकों के संयोजन ने इस समय भारत को विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। इसके अलावा, मजबूत घरेलू बुनियादी तत्व इस नए रुझान का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, देश में मुद्रास्फीति निम्न स्तर पर बनी हुई है, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है। इससे पहले मई में शुद्ध एफपीआई प्रवाह सकारात्मक रहा और 19,860 करोड़ रुपये रहा। इससे मई विदेशी निवेश के मामले में इस साल अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला महीना बन गया।

8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को बड़ी राहत! अब 12 साल में बहाल हो सकती है पूरी पेंशन

नई दिल्ली । केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है. अब कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग जोर पकड़ चुकी है. यह मांग कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल की ओर से सरकार को दी गई चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा है. अगर यह मांग मानी जाती है, तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्दी पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (लम्प सम) लेने का विकल्प मिलता है. इसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहा जाता है. इसके बदले में हर महीने मिलने वाली पेंशन से एक तय राशि काट ली जाती है, ताकि सरकार उस लम्प सम रकम की भरपाई कर सके. फिलहाल ये कटौती 15 साल तक होती है, यानी 15 साल बाद ही कर्मचारी को उसकी पूरी पेंशन मिलती है. कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स का कहना है कि 15 साल की अवधि बहुत लंबी और आर्थिक रूप से नुकसानदेह है. आज के समय में ब्याज दरें काफी कम हो गई है, जबकि कटौती का फॉर्मूला

पुराना है.

इससे रिटायर्ड कर्मचारी अपनी ही पेंशन का बड़ा हिस्सा खो बैठते हैं. अगर ये अवधि 12 साल की कर दी जाए, तो रिटायर्ड लोगों को जल्दी से पूरी पेंशन मिल सकेगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, खासकर उस समय जब स्वास्थ्य, महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं. नेशनल काउंसिल ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की सूची सौंपी है. इसमें सबसे बड़ी मांग यही है, कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए. सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग के ToR में शामिल किया जा सकता है. इससे उम्मीद और मजबूत हो गई है कि यह बदलाव वाकई लागू हो सकता है. 11 मार्च 2025 को हुई SCOVA (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक में भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठा. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, पेंशन एवं जन शिकायत) ने की. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी माना कि मौजूदा सिस्टम को ज्यादा न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है. इसके बाद यह तय किया गया कि यह मांग वेतन आयोग के एजेंडे में शामिल होगी. फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. परंपरा के अनुसार नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, लेकिन आयोग के सदस्यों के नाम और अध्यक्षअभी तय नहीं हुए है. इससे संकेत मिल रहे है कि इसमें कुछ देरी हो सकती है. लेकिन कम्युटेड पेंशन बहाली का मुद्दा अब प्राथमिकता में आ गया है. सरकार अगर कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि 12 साल कर देती है, तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए राहत की सांस होगी. भले ही 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में समय लग रहा हो, लेकिन इस दिशा में उठाया गया हर कदम सरकारी सेवा दे चुके लोगों के सम्मान और हक का प्रतीक होगा. इसके अलावा, रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पूरी पेंशन जल्द मिल जाएगी. उनको स्वतंत्र आर्थिक स्थिति में मदद मिलेगी. स्वास्थ्य, पारिवारिक खर्चों और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना आसान होगा और पहले से रिटायर्ड पेंशनर्स को भी राहत मिल सकती है (अगर नियम को पीछे से लागू किया गया).

ट्रंप ने लाखों भारतीयों को दी राहत, रेमिटेंस टैक्स घटाकर किया 1 फीसदी ; इस तरह पैसे भेजने पर 0 टैक्स

नई दिल्ली। अमेरिका में रहकर नौकरी कर रहे लाखों भारतीयों के लिए राहत भरी खबर है। इतना ही नहीं इसमें भी अगर कोई भारतीय NRI बैंक खातों, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे भेजता है तो उसपर 0 टैक्स लगेगा। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट को संशोधित करके Remittance Tax कम किया गया है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल के संशोधित मसौदे में प्रस्तावित पैसे ट्रांसफर करने पर पहले से प्रस्तावित 3.5व टैक्स को घटाकर मात्र 1फीसदी कर दिया गया है। ट्रंप सरकार के इस कदम से अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को राहत मिली है। यह बिल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव से पारित हो गया है। सीनेट रिपब्लिकन ने 27 जून को इस बिल का अपडेटेड ड्राफ्ट जारी किया। डिबेट के बाद सीनेट से बिल पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इस प्रोसेस को 4 जुलाई तक पूरे होने की उम्मीद है। 27 जून, 2025 को जारी किए गए संशोधित विधेयक के अनुसार रेमिटेंस टैक्स को पहले प्रस्तावित 3.5 फीसदी से घटाकर मात्र 1 फीसदी कर दिया गया है। इसमें बैंक खातों, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर पैसे भेजे गए पैसे को इस टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी गई है। लेकिन अगर आप नकद, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक या अन्य समान भौतिक साधनों के जरिए पैसे भेजते हैं तो आपको इसके लिए 1 फीसदी का टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं तो आपको अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड या किसी वित्तीय संस्थान के खाते के माध्यम से पैसे भेजने होंगे। वन बिग ब्यूटीफुल बिल में संशोधन गैर-निवासी भारतीयों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। लाखों भारतीय अमेरिका में रहकर नौकरी करते हैं और हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। ऐसे में उनके लिए यह संशोधित बिल राहत भरी सांस लेकर आया है। अंतरराष्ट्रीय कर विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। ग्रांट थॉर्नटन भारत के यूएस टैक्स पार्टनर लॉयड पिंटो ने कहा, -सीनेट के नवीनतम ड्राफ्ट ने रेमिटेंस टैक्स को 3.5फीसदी से घटाकर 1फीसदी कर दिया है। साथ ही, अमेरिकी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के खातों या अमेरिका में जारी डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए रेमिटेंस को टैक्स से छूट दी गई है। यह भारतीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इससे पहले मई 2025 में इस बिल में प्रस्तावित 5 फीसदी रेमिटेंस टैक्स को घटाकर 3.5 फीसदी किया गया था। लेकिन अब एक बार इसे फिर से संशोधित करके 1 फीसदी कर दिया गया है। और साथ ही बैंक अकाउंट व कार्ड्स के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर टैक्स में छूट भी दे दी गई है। यह बिल 31 दिसंबर 2025 से लागू होगा। यानी इस बिल के तहत लगने वाला टैक्स 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

अनंत अंबानी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सालाना मिल सकता है 20 करोड़ तक वेतन

नई दिल्ली ।

भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी को कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इस नई जिम्मेदारी के तहत अब उन्हें सालाना 10 से 20 करोड़ रुपये तक का वेतन, कई तरह के भत्ते और कंपनी के मुनाफे में से कमीशन भी मिलेगा। रिलायंस ने शेयरधारकों को भेजी गई एक नोटिस में बताया है कि अनंत को घर, यात्रा, चिकित्सा, सुरक्षा, और परिवार सहित खर्चों की भरपाई सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्हें बिजनेस ट्रिप के दौरान पत्नी व सहायकों के साथ यात्रा और रहने का खर्च भी कंपनी उठाएगी। बता दें कि 2023 में मुकेश अंबानी ने अपने तीनों बच्चों आकाश, ईशा और अनंत को कंपनी के बोर्ड में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में शामिल किया था। तब उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, केवल बैठक में शामिल होने का 4 लाख रुपये का शुल्क और करीब 97 लाख रुपये का मुनाफे पर कमीशन दिया गया

था। हालांकि अब कार्यकारी निदेशक बनने के बाद 30 वर्षीय अनंत को पूरा वेतन मिलेगा। इसको लेकर रिलायंस ने कहा है कि उन्हें ऑयल-टू-केमिकल, न्यू एनर्जी, विनाइल, स्पेशलिटी पॉलिएस्टर, और गिगाफैक्ट्रीज जैसे प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है। देखा जाए तो अनंत 2015 से रिलायंस समूह से जुड़े है।

उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है और कंपनी के एनर्जी बिजनेस, खासकर सोलर और रिन्युएबल प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभा रहे है। वे रिलायंस फाउंडेशन और वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट वनतारा से भी जुड़े हैं। गौरतलब है कि रिलायंस के उत्तराधिकार की योजना के तहत तीनों अंबानी बच्चे आकाश, ईशा और अनंत को अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स की जिम्मेदारी दी गई है। आकाश अंबानी जियो इंफोकॉम के चेयरमैन है। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल और ई-कॉमर्स की जिम्मेदारी संभाल रही है। तो वहीं अनंत अंबानी ऊर्जा और केमिकल कारोबार में अहम भूमिका निभा रहे है।